



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]

नहीं दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22, 1977/आश्विन 30, 1899

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 1977/ASVINA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

માગ II—ખણ્ડ 3—ઉપ-ખણ્ડ (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांघिक प्रावेश और प्रधिसचनाएं

**Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities**

विधि, न्याय और कल्पनी कार्य मंशालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1977

का०ओ 3259.—एकाधिकार एवं निवंशनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपशारा (3) के अनुसरण में केवल सरकार एनदब्ल्यूएस में दि अमिट प्रोडक्ट्स लिमिटेड के, इस धारा के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं 245/70) के विलोपन को इस प्रविधिन्थ के आधार पर अधिसूचित करती है कि यह विलोपन वेतव्य उस समय तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कम्पनी, एकाधिकार एवं निवंशनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2(र) की सीमा से परे रहे तथा यह कम्पनी के किसी ऐसे कार्य कलाप के प्रारम्भ कर दिए जाने पर, जिससे कि वह अधिनियम की धारा 2(र) में दिए गए एक उपक्रम की परिभाषा को आकर्षित करती हो, के तुरन्त स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएगा।

[सं० 2/23/76-एम-2]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 3rd October, 1977

S.O. 3259.—In pursuance of sub-section (3) of section 25 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s The Amit Products Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 245/70) subject to the condition that the cancellation will be effective only until such time that the company continues to be outside the purview of section 2(v) of the M. R. T. P. Act and will be automatically in-effective no sooner than the Company starts any other activity which would attract the definition of an undertaking given in section (v) of the Act.

[F. No. 2/23/76-M.II]

C. KHUSHALDAS, Dy. Secy.

वित्त भवालय

(आधिकारिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1977

(बैंकिंग प्रभाग)

का०आ० 3260.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्ड्रुडारा अम्पुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० एन० जैन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-12/75-ए० सी० में निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-12/75-ए० सी०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th September, 1977

BANKING DIVISION

S.O. 3260.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-12/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri S. L. Jain as the Chairman of the Jaipur Nagpur Aanchalik Gramin Bank, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-12/75-AC]

का०आ० 3261.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्ड्रुडारा हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० कै० खन्ना की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-14/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-14/75-ए० सी०]

S.O. 3261.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking Wing, No. F. 4-14/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri S. K. Khanna as the Chairman of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-14/75-AC]

का०आ० 3262.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्ड्रुडारा प्रथमा बैंक, मुरादाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० दस्तगीर की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-15/75-ए० सी० में निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-15/75-ए० सी०]

S.O. 3262.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-15/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri S. R. Dastgir, Chairman of the Prathma Bank, Moradabad, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-15/75-AC]

का०आ० 3263.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्ड्रुडारा भगीरथ ग्रामीण बैंक, मीनापुर (उ० प्र०) के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० ए० राय की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-58/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-58/76-ए० सी०]

S.O. 3263.—In exercise of the powers conferred by section 11, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-58/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri B. N. Rai, as the Chairman of the Bhagirath Gramin Bank, Sitapur (U.P.), namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-58/76-AC]

का०आ० 3264.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्ड्रुडारा सातथ मलाबार ग्रामीण बैंक, मलम्पुरम के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० कल्याकर मौटटी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-60/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-60/76-ए० सी०]

S.O. 3264.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-60/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri A. Karunakara Shetty, as the Chairman of the South Malabar Gramin Bank, Malappuram, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-60/76-AC]

का० आ० 3265.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनदब्ल्यूआर चम्पारण खेत्रीय ग्रामीण बैंक मोरीज़ारी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक भारत मरकार राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-69/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-69/75-ए० सी०]

S.O. 3265.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-69/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Shiv Sharma as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977", the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-69/75-AC]

का० आ० 3266.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनदब्ल्यूआर-रोहताम ग्रामीण बैंक, भारा के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० कौ० जैन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-70/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं० एफ० 4-70/75-ए० सी०]

S.O. 3266.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-70/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri P. K. Jain, as the Chairman of the Bhojpur Rohtas Gramin Bank, Arrah, namely :

In the said notification, for the figures letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-70/75-AC]

का० आ० 3267.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० कोतवाल की नियुक्ति विषयक भारत मरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-72/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-72/75- ए० सी०]

S.O. 3267.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-72/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri S. R. Kotwal, as the Chairman of the Jammu Rural Bank, Jammu, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-72/75-AC]

का० आ० 3268.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनदब्ल्यूआर तुंग भवा ग्रामीण बैंक, बेलारी के अध्यक्ष के रूप में श्री श्री० ए० प्रभु को नियुक्ति विषयक भारत मरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-73/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 4-73/75 ए० सी०]

S.O. 3268.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-73/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri B. A. Prabhu, as the Chairman of the Tungabhadra Gramin Bank, Bellary, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-73/75-AC]

का० आ० 3269.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनदब्ल्यूआर भयुराशी ग्रामीण बैंक, सूरी के अध्यक्ष के रूप में श्री कौ० जैन जैन की नियुक्ति विषयक भारत मरकार राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-75/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-75/76- ए० सी०]

S.O. 3269.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-75/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K. S. Banerjee, as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank, Suri, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-75/76-AC]

का० आ० 3270.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लारा कटक ग्रामीण बैंक, कटक के अध्यक्ष के रूप में श्री विष्णु चन्द्र दाम की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-76/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थत्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-76/76-ए० सी०]

S.O. 3270.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-76/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Swarup Chandra Dash, as the Chairman of the Cuttack Gramya Bank, Cuttack namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-76/76-AC]

का० आ० 3271.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लारा बुलतानपुर खेतीय ग्रामीण बैंक, बुलतानपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश प्रसाद द्वारे की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-77/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थत्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-77/76-ए० सी०]

S.O. 3271.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-77/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Jagdish Prasad Dubey, as the Chairman of Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-77/76-AC]

का० आ० 3272.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लारा ग्रामीण बैंक, गया के अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश प्रसाद की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-79/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थत्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-79/75-ए० सी०]

S.O. 3272.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-79/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri G. C. Kalita, as the Chairman of the Pragyotish Gaonlia Bank, Nalbari, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words, "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-79/75-AC]

का० आ० 3273.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लारा बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शारदा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-79/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थत्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-79/76-ए० सी०]

S.O. 3273.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-79/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri H. M. Sharda, as the Chairman of the Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-79/76-AC]

का० आ० 3274.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लारा भग्न ग्रामीण बैंक, गया के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० के० प्रसाद की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-80/77 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थत्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-80/76-ए० सी०]

S.O. 3274.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-80/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri R. K. Prasad as the Chairman of the Magadh Gramin Bank, Gaya, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-80/76-AC]

का० आ० 3275.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा ग्रामीण ग्रामीण बैंक, सीकर के प्रध्यक्ष के रूप में श्री आर० जी० पुरी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, गजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-81/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों अधरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-81/76-ए० सी०]

S.O. 3275.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-81/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri R. G. Puri as the Chairman of the Shekhawati Gramin Bank, Sikar, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-81/76-AC]

का० आ० 3276.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रधिनियम, 1976 (1976 का 21) धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मारवाड़ ग्रामीण बैंक पाली के प्रध्यक्ष के रूप में श्री बलराम मिश्र की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-82/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-82/76-ए० सी०]

S.O. 3276.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-82/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Balram Mishra, as the Chairman of the Marwar Gramin Bank, Pali, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-82/76-AC]

का० आ० 3277.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रायपार्हीमा ग्रामीण बैंक, कुड़डापेह के प्रध्यक्ष के रूप में श्री हृषा मारवर कुण्डे की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-83/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 के अंकों, अधरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-83/76-ए० सी०]

S.O. 3277.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-83/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Kuru-passagar Kunde, as the Chairman of the Royalaseema Gramineen Bank, Cuddapah, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-83/76-AC]

का० आ० 3278.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरनल्ला के प्रध्यक्ष के रूप में श्री मानबेंद्र सेन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-84/75 एस० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-84/75-ए० सी०]

S.O. 3278.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-84/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Manabendra Sen as the Chairman of the Tripura Gramin Bank, Agartala, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-84/75-AC]

का० आ० 3279.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम के प्रध्यक्ष के रूप में श्री चौ० आर० के० पटनायक की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-84/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अधरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-84/76-ए० सी०]

S.O. 3279.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-84/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri D. R. K. Patnaik as the Chairman of the Sri Vishakha Gramena Bank, Srikakulam, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-84/76-AC]

का० आ० 3280.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० सी० बुद्धिराज की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-85/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[स० एफ० 4-85/75-ए० सी०]

S.O. 3280.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-85/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri R. C. Budhiraja as the Chairman of the Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-85/75-AC]

का० आ० 3281.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा कोमी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया के अध्यक्ष के रूप में श्री कें० एन० शुक्ल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-85/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-85/76-ए० सी०]

S.O. 3281.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-85/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K. N. Shukla, as the Chairman of the Kosi Kshetriya Gramin Bank, Purnea, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-85/76-AC]

का० आ० 3282.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० शी० बालगोपाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-86/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-86/76-ए० सी०]

S.O. 3282.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-86/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of the Shri H. G. Balagopal as the Chairman of the Cauvery Gramenea Bank, Mysore, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31 December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-86/76-AC]

का० आ० 3283.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा बोलगीरी आंचलिक ग्रामीण बैंक, बोलगीरी के अध्यक्ष के रूप में श्री गोलक बिहारी मार्गी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-86/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-86/75-ए० सी०]

S.O. 3283.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-86/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Golak Bihari Sarangi as the Chairman of the Bolangir Aanchalik Gramya Bank, Bolangir, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-86/75-AC]

का० आ० 3284.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा मालप्रभा ग्रामीण बैंक भारतार के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० शी० इनामदार की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना स० एफ० 4-87/76-ए० सी० में निम्ननिश्चित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 अक्टूबर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-87/76-ए० सी०]

S.O. 3284.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-87/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri M. V. Inumdar, as the Chairman of the Malaprabha Grameena Bank, Dharwar, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-87/76-AC]

का० आ० 3285 —प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लार युर्ग ग्राम्य बैंक, पिपली के अध्यक्ष के रूप में श्री मुरेन्द्र महानी थीं नियुक्ति विधायक भारत सरकार, गजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-87/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थतः—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-87/75-ए० सी०]

S.O. 3285.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-87/75-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri Surendra Mahanty, as the Chairman of the Puri Gramya Bank, Pipili, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-87/75-AC]

का० आ० 3286.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लार कोरगपूट पंचवटी ग्राम्य बैंक जैपोर के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० नायक की नियुक्ति विधायक भारत सरकार, गजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-88/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थतः—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-88/76-ए० सी०]

S.O. 3286.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-88/76-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri P. Nayak as the Chairman of the Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jeypore, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-88/76-AC]

का० आ० 3287.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लार वैलिया खंकीय ग्रामीण बैंक, खंकीय के अध्यक्ष के रूप में श्री डॉ आ० ग्राम० काथुरिया की नियुक्ति विधायक भारत सरकार, गजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-89/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थतः—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-89/76-ए० सी०]

S.O. 3287.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-89/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri D. R. Kathuria, as the Chairman of Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-89/76-AC]

का० आ० 3288.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लार कर्स्याबाद ग्रामीण बैंक, कर्स्याबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री रघबीरचन्द्र खन्ना की नियुक्ति विधायक भारत सरकार, गजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-90/75-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थतः—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-90/75-ए० सी०]

S.O. 3288.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-90/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Raghbir Chand Khanna, as the Chairman of the Furrakhabad Gramin Bank, Furrakhabad, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-90/75-AC]

का० आ० 3289.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के माथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एन्डब्लार नार्वे भानाबाद ग्रामीण बैंक, कन्नानूर के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० एम० दमोदरन की नियुक्ति विधायक भारत सरकार, गजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-90/76 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रार्थतः—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-90/76-ए० सी०]

S.O. 3289.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-90/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri A. N. Dattodaran Nair, as the Chairman of the North Malabar Gramin Bank, Cannanore, namely :

In the said notification for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-90/76-AC]

का० आ० 3290.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ के अध्यक्ष के रूप में श्री हसन किश्वर्ह की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की प्रधिमूचना सं० एफ० 4-91/75—ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रधिमूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-91/75-ए० सी०]

S.O. 3290.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) No. F. 4-91/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Hasan Kidwai, as the Chairman of the Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh, namely :

In the said notification, for the figures letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-91/75-AC]

का० आ० 3291.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली के अध्यक्ष के रूप में श्री श्याम चन्द्र सोनी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की प्रधिमूचना सं० एफ० 4-92/75—ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रधिमूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-92/75-ए० सी०]

S.O. 3291.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking (Banking Wing), No. F. 4-92/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Shyam Chandra Soni, as the Chairman of the Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank, New Delhi.

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-92/75-AC]

का० आ० 3292.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी के अध्यक्ष के रूप में श्री कंवर कीरन्द्र निरू की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की प्रधिमूचना सं० एफ० 4-93/75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रधिमूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-93/75-ए० सी०]

S.O. 3292.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-93/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Kanwar Virendra Singh Gupta as the Chairman of the Barabanki Gramin Bank, Barabanki namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-93/75-AC]

का० आ० 3293.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भल्लुम ग्रामीण बैंक, बाकुग के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की प्रधिमूचना सं० एफ० 4-94/75—ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त प्रधिमूचना के 30 सितम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-94/75-ए० सी०]

S.O. 3293.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-94/75-AC, dated the 31st March, 1977 relating to the appointment of Shri Pratap Chakraborty as the Chairman of the Mallabhum Gramin Bank, Bankura, namely :

In the said notification, for the figures, letters, and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-94/75-AC]

का० आ० 3294.—प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संयुक्त परगना ग्रामीण बैंक, दुमला के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० क० शोप की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1977 की प्रधिमूचना सं० एफ० 4-134/76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त प्रधिमूचना के 30 सितम्बर, 1977 के अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-134/76-ए० सी०]

S.O. 3294.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of

Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-134/76-AC, dated the 30th March, 1977 relating to the appointment of Shri B. K. Ghosh as the Chairman of the Santhal Parganas Gramin Bank, Dumka, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-134/76-AC]

का० आ० 3295.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवर्त गतियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा ग्रामीण बैंक, भारतीय अध्यक्ष के रूप में श्री के० एस० राजेन्द्र पात्र की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-136/76—ए० सी० में निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 में, अध्यक्ष, अध्यक्ष, और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 में, शक्ति, शक्ति और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-136/76-ए० सी०]

S.O. 3295.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-136/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri K. S. Rajput, as the Chairman of the Himachal Gramin Bank, Mandi, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-136/76-AC]

का० आ० 3296.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रवर्त गतियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा ग्रामीण बैंक, रीवा के अध्यक्ष के रूप में श्री वी० डी० नारंग की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-139/76—ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 सितम्बर, 1977 में, अध्यक्ष, अध्यक्ष, और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1977 में, शक्ति, शक्ति और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-139/76-ए० सी०]

सी० आ० ४० विस्वाम, उप-सचिव

S.O. 3296.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), No. F. 4-139/76-AC, dated the 30th June, 1977 relating to the appointment of Shri B. D. Narang, as the Chairman of the Rewa-Sidhi Gramin Bank, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th September, 1977" the figures, letters and words "31st December, 1977" shall be substituted.

[No. F. 4-139/76-AC]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

94 GI/77—2

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1977

का० आ० 3297.—भारतीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (5) के प्रनूत्तर में केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के निदेशक श्री हितेन भाया को 3 अक्टूबर, 1977 से भारतीय ग्रामीण बैंक का निवेशक नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 19(69) आई० एफ० 1/77]

वी० के० शुग्ल, निवेशक

New Delhi, the 3rd October, 1977

S.O. 3297.—In pursuance of sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri Hiten Bhaya, Director Indian Institute of Management, Calcutta as the director of the Industrial Development Bank of India with effect from the 3rd October, 1977.

[No. F. 10(69) IF. I/77]

V. K. SHUNGLU, Director

उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मद्रास

मद्रास, 30 सितम्बर, 1977

सीमाशुल्क

का० आ० 3298.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के उप-खण्ड (ग) खण्ड 152 के अन्तर्गत, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा) नई दिल्ली से जारी की गयी अधिसूचना संख्या 79/सीमाशुल्क VII तारीख 18 जुलाई 1975 में दिये हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क समाहर्ता, मद्रास, जो वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग) से अधिसूचना संख्या 37 सीमाशुल्क दिनांक 1 फरवरी, 1963 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत "सीमाशुल्क समाहर्ता भी नियुक्त है" तमिलनाडु राज्य के नार्थ आरकाड जिले में विनियमाड़ी तालूक के "सीलूर प्राम" को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के खण्ड 9 के अन्तर्गत (1962 का 52) "भाष्टापार स्टेशन" घोषित करते हैं ।

[सं० सी० नं० VIII/40/8/77 सीमाशुल्क नीति]

ए० जे० राव, समाहर्ता

The Madras Central Excise Collectorate, Madras

Madras, 30th September, 1977

CUSTOMS

S.O. 3298.—In exercise of the powers conferred by Notification No. 79/Customs VII dated 18th July, 1975 issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise, Madras also appointed as "Collector of Customs" within the jurisdiction of the Madras Central Excise Collectorate by Government of India in Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 37 Customs dated the 1st February, 1963 hereby declares SOLUR VILLAGE of Vaniambadi Taluk, North Arcot District in the State of Tamil Nadu to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[C. No. VIII/40/8/77 Cus. Pol.]

I. J. RAO, Collector

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 1 जून, 1977।

आय-कर

का० आ० 3299—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपकारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-न्यूनता पर यातांशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679/का० सं० 187/2/74—आई टी (ए 1), तारीख 20 जून 1974 में उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

I. इससे उपाबद्ध अनुसूची के क्रम सं० 21-ब तमिलनाडू III मद्रास के सामने स्तंभ 3 में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी,

“13 पुडुकोट्टै नक्षित”

II. इससे उपाबद्ध अनुसूची के क्रम सं० 21-ब तमिलनाडू, मद्रास के सामने स्तंभ 3 में क्रम सं० 10 के सामने की विवरान प्रविष्टि “पर्याप्ति” “पुडुकोट्टै नक्षित” का लोप किया जाएगा। क्रम संख्या 11 से 16 को क्रमशः 10 से 15 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

यह अधिसूचना 4-6-1977 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1801/का० सं० 187/13/77-आई टी (ए 1)]

एम० शास्त्री, प्रबंध मंत्रिय

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th June, 1977

INCOME-TAX

S. O. 3299.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its notification No. 679 (F. No. 187/2/74-IT(AI) dated the 20th July, 1974 as amended from time to time :—

I. Against S. No. 21-B Tamil Nadu-III, Madras under column 3 of the Schedule appended thereto, the following entry shall be added :

13. Pudukkottai Circle.

II. Against S. No. 21-C Tamil Nadu-IV, Madras under column 3 of the Schedule appended thereto, the existing entry against Serial Number 10 viz., Pudukkottai Circle shall be deleted. Serial Number 11 to 16 shall be re-numbered 10 to 15.

This notification shall come into force on the 4-6-1977.

[No. 1801/F. No. 187/13/77-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

वारिष्ठ अधिकारी

संयुक्त मूल्य विवरण, आयात-नियांता का कार्यालय

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

का० आ० 3300—महेन्द्रा गण्ड महेन्द्रा लि०, धाटकोपर, कण्डीवली, बम्हाई को वास्तविक उपभोक्ता साइरेस मंख्या पी/लि/2197910, दिनांक 27-4-74 के प्रमुखार कच्चा माल तथा संपर्कों को आयात करने के लिए 3,46,223/- रुपए मात्र के लिए भारईपी आयात लाइसेंस संख्या पी/एल/1772769/0, दिनांक 31-3-75 प्रदान किया गया था।

आयात आपार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1976-77 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ी जाने वाली कांडिका 320 के प्रन्तर्गत उन्होंने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह शपथ भी है कि पूर्वोत्तर लाइसेंस की बोनों प्रतिया (सीमा शालक प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति) किसी भी सीमा शूलक सदन के पास पंशीकृत कराएं बिना और बिल्कुल ही उपयोग में लाए बिना ही द्वां गई/अस्थानस्थ हो गई है। पार्टी ने उक्त लाइसेंस (सीमा शूलक प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति) के पूर्ण मूल्य 3,46,223/- रुपए मात्र के लिए अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है और इस बात का आव्यासन किया है कि मूल लाइसेंस यहि बाद में प्राप्त हो गया तो इस कार्यालय को वापस लौटा दिया जाएगा।

मैं गत्युष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस संख्या पी/एल/1772769/0, दिनांक 31-3-75 (सीमा शूलक प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों) खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। अतः (ग्रन्तीनं तथा संशोधित) आयात नियंत्रण आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सीसी) के प्रन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग कर, मैं पूर्वोत्तर लाइसेंस (दोनों सीमा शूलक तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों) को एनद्वारा रद्द करने का आदेश देता हूँ। पूर्ण मूल्य 3,46,223/- रुपए मात्र के लिए पूर्वोत्तर लाइसेंस (सीमा शालक प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति) की अनुलिपि प्रतिया अलग से जारी कर दी गई है।

[मि० मं० इन्जी० 259/जे-एस-74/एमसी-2/सीएएग से जारी
एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते भयुत्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF

IMPORTS & EXPORTS

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 31st January, 1977

S. O. 3300.—M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Ghatkopar, Kandivali, Bombay were granted REP import licence No. P/L/1772769/C dated 31-3-1975 for Rs. 3,46,223 only for import of Raw Materials and Components as per A/U licence No. P/D/2197910 dated 27-4-1974.

They have filed an affidavit as required under para 320 read with Appendix 8 of the ITO Hand Book of Rules & Procedure 1976-77 wherein they have sworn in that both copies (Customs Purposes & Exchange Control) of the aforesaid licence has been lost/misplaced without having been registered with any Customs House & utilised at all. The firm have applied for duplicate copies (Customs Purposes & Exchange Control) of the said licence for the full value of Rs. 3,46,223/- only and given an undertaking to return the original licence to this office if traced out later on.

I am satisfied that the original licence No. P/L/1772769/C dated 31-3-1975 (both Customs Purposes Copy & Exchange Control Copy) has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the power conferred on me under clause 9(c) of the Import Control Order 1955 dated 7-12-1955 (as amended up to date), I hereby order the cancellation of the aforesaid licence (both Customs & Exchange Control Copies).

Duplicate copies of the above mentioned licence (Customs Purposes & Exchange Control) for the full value of Rs. 3,46,223/- only has been issued separately.

[Issued from file No. Engg. 258/JS-74/SC II/CLA]

M. G. GOMBER, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller.

मुख्य नियंत्रक, आयात-विर्यात का कार्यालय, भैंड विल्सी

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1977

क्रा० आ० 3301.—सर्वेश्वी मार्शल भन्न एण्ड कं० मैन्युफूर्सर्सिंग न्य० संख्या 9 सेकेण्ड लाइन बीच, मद्रास-600001 का स्वीडिंग माल से मलान सूची के अनुगाम कच्चे माल/संघटकों के आयात के लिए ९३,१००/- रुपए के लिए लाइसेंस संख्या पी/टी/2202328/आर/एम इन्व्यू/५७/एच/४१-४२, दिनांक 12-९-७५ प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने पूर्वोक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति के अनुनियिंग के लिए इस आधार पर निवेदन किया है कि उन से मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति, सीमाशुल्क मदन, मद्रास, में पंजीकृत करने के पश्चात् खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी ने आगे यह सूचना दी है कि लाइसेंस में १३,४३७/- रुपए की धनराशि शेष है।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक गणधर्म दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से मंतुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या पी/टी/2202328/दिनांक 12-९-७५ की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुनियिंग आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्वारा रद्द की जानी है।

4. सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुनियिंग अलग से जारी की जाए है।

[संख्या मंके/एम-1(1)/एम-76/आर.एम-4/697]

एन० प० कोहली, उप-मुख्य नियंत्रक
कूले मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports and Exports
New Delhi

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1977

S.O. 3301.—M. & Marshall, Sons & Co. Mfg.) Limited, No. 9 Second Line Beach, Madras-600001 were granted import licence No. P/D-2202328/R/SW/57/H/41-42 dated 12-9-1975 for import of Raw materials/components as per list attached to it valued at Rs. 93,100/- from Swedish Credit.

2. They have requested for the issue of Duplicate Customs purposes copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost or misplaced after having been registered with the Customs, Madras. It has been further reported by the licence that the licence had an unutilised balance of Rs. 13,437/-.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. P/D-2202328 dated 12-9-1975 has been lost or misplaced and hence directs that a Duplicate Customs Purposes copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy is hereby cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[File No. Mach/M-1(1)/AM76/RM4/697]
N. A. KOHLY, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

क्रा० आ० 3302.—दि० पी० एण्ड ई० कॉर्पोरेशन इण्डिया न्य०, नई दिल्ली का २,९४,७००/- रुपए जापान से इकोगोक्सिंग किंग पाउडर का आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या पी/टी/7500180 दिनांक

26-2-69 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियों की अनुनियिंग प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे उक्त लाइसेंस की दोनों मूल प्रतियों खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। लाइसेंसधारी ने आगे यह भी बताया है कि लाइसेंस सीमाशुल्क मदन, बम्बई में पंजीकृत कराया गया है और प्राप्तिक रूप में उपयोग में लाया गया है। ऐप धनराशि १९,६७४/- रुपए के लिए धब्ब अनुनियिंग प्रति की आवश्यकता है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक गणधर्म प्रति किया है। अधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/टी/2500180/दिनांक 26-2-69 की दोनों प्रतियों खो गई हैं तथा निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियों उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की दोनों प्रतियों प्रति लाइसेंस रद्द की जाती है।

लाइसेंस संख्या पी/टी/2500180, दिनांक 26-2-69 की दोनों प्रतियों अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एस०टी०८००/एम०आर०एम०सी०/६८/७७/६८-६९/

आर०ए०स०सेल०/१८७]

प्र० क० शर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3302.—The P. & E. Corp. of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/2500180, dated 26-2-69 for the Import of Echosounder Fish Finder etc. from Japan to the value of Rs. 2,94,700/-. They have requested for the issue of duplicate both copies of the above licence on the ground that are Original both copies of the above licence has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence has been registered with Customs House Bombay and utilized partly. The duplicate copy now required is to cover the balance of Rs. 19,674/-.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that both the copies of licence No. G/T/2500180, dated 26-2-1969 have been lost and directs that both copies of the said licence should be issued to them. The both the copies of the licence are hereby cancelled.

Both copies of the licence No. G/T/2500180 dated 26-2-1969 are being issued separately.

[File No. STC/MISC-68-77/68-69/RM Cell/187]

A. K. SHARMA, Dy. Chief Controller.

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977

क्रा० आ० 3303.—सर्वेश्वी गर्ड्वरे प्लास्टिक प्रा० न्य०, बम्बई का १६,०७,८९५/- रुपए (छियालिम लाख सात हजार आठ सौ पंचानवे रुपए माल) के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/सी०१०/२०६७१४७/एम०आर०टी०/५१/एच/३७-३८, दिनांक 30-4-1974 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुनियिंग प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की मूल प्रति सीमाशुल्क प्राप्तिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराई गई थी और प्राप्तिक रूप से उपयोग में लाई गई थी। यह १५,४३,६४३/- रुपए के लिए उपयोग में लाई गई थी और दिनांक 18-८-1977 को उग पर ६४,२१२/- रुपए की धनराशि ऐप है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने अनियिक सुध्य महानगरीय प्रजिस्टेट, बन्दा, बम्बई, के सम्मुख विधिवत गणधर्म लेकर एक गणधर्म

दाखिल किया है। तबनुसार, मैं सत्त्वर्ष हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रवत्त प्रवत्त अधिकारों का उपयोग कर सर्वेश्वी गरवारे प्लास्टिक प्रा० लि०, बम्बई को जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या पी०सी०/2067147/एस/आईवी/51/एच/37-38/सीजी-3, दिनांक 30-4-1974 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अब अलग से लाइसेंसधारी को जारी की जा रही है।

[संख्या सी जी-3/21/(105)/73-74/1511]

चन्द्र गुप्त, उप-मूल्य नियंत्रक,

कृते मुख्य-नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1977

S.O. 3303.—M/s. Garware Plastics Ltd., Bombay were granted an Import Licence No. P/CG/2067147/S/IB/51/H/37-38 dated 30-4-1974 for Rs. 46,07,895 (Rupees Forty six lakhs seven thousand eight hundred and ninety five only). They have applied for issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes was registered with the Customs authorities at Bombay and utilised partly. It was utilised for Rs. 45,43,683 and the balance available on it was Rs. 64,212 as on 18-8-1977.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly affirmed before the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Bandra, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the power conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy of licence No. P/CG/2067147/S/IB/51/H/37-38/CG. III dated 30-4-1974 issued to M/s. Garware Plastics Pvt. Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licence.

[No. CG. III/21/(105)/73-74/1511]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller
for Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रण का कार्यालय, मद्रास

मद्रास, 6 प्रगस्त, 1977

आदेश

कां था० 3304.—सर्वेश्वी इन्सूलेटर्स एस० इनस्युलेटर्स एस०, पोरूर, मद्रास-602104 को सामान्य मूदा क्षेत्र से उक्त लाइसेंस के लिये संलग्न अनुबन्ध में यथावर्णित कच्चे माल एवं संबटकों के आयात के लिये लाइसेंस संख्या पी०/एम०/2779916/सी०/एस०/57/एम०/41-42 दिनांक 10-12-75 जारी किया गया था। उक्त लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मूदा विनियम नियंत्रण प्रति जारी करने के लिये अब इस आधार पर आदेश किया है कि लाइसेंस की मूदा विनियम प्रति मद्रास सीमा शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत कराने के और अंशतः उपयोग में लाने के पासात् ताक मार्ग में खो गयी है। कुल मूल्य जिसके लिये लाइसेंस जारी किया गया था वह 1,27,217 रुपये है और कुल मूल्य जिस को पूरा करने के लिये अब अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह 16,226.00 रुपये है। अपने तर्क के समर्थन में आदेश कर्म ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं सत्त्वर्ष हूँ कि लाइसेंस संख्या पी०/एम०/2779916/सी०/एस०/57/एम०/41-42 दिनांक 10-12-75 की मूल मूदा विनियम नियंत्रण

प्रति खो गई है और नियेश देता हूँ कि आवेदन को लाइसेंस की अनुलिपि मूदा विनियम नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिये। आयात लाइसेंस संख्या पी०/एम०/2779916/सी०/एस०/57/एम०/41-42, दिनांक 10-12-75 की मूल मूदा विनियम नियंत्रण प्रति को एतद्वारा किया जाता है।

[मिसिल संख्या ई०/जी/एडवा ला०/2/ओडी-75/आर ई० पी०-2 से जारी]

प्राई० ए० रशीद, उप-मूल्य नियंत्रक,

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports,
Madras

ORDER

Madras, the 6th August, 1977

S.O. 3304.—M/s. W. S. Insulators of India Limited, Porur, Madras-602104 were issued an import licence No. P/M/2779916/C/XX/57/M/41-42 dt. 10-12-1975 for import of raw materials and components as detailed in the annexure attached to the said licence under General Currency Area. The said licence holder have now applied to this office for the issue of Duplicate of the Exchange Control Copy of the said import licence on the ground that the Exchange Control Copy of the licence has been lost in postal transit after having been registered with Madras Custom House and utilised partly. The total amount for which the licence was issued is Rs. 1,27,217 and the total amount for which the duplicate copy is now required is to cover the balance Rs. 16,226.00. In support of their contention the applicant firm has filed an affidavit.

I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the Import licence No. P/M/2779916/C/XX/57/M/41-42/dt. 10-12-1975 has been lost and direct that a duplicate Exchange Control Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy of the import licence No. P/M/2779916/C/XX/57/M/41-42/dt. 10-12-75 is hereby cancelled.

[Issued from file No. Engg/Adv. Lic. /2/OD. 75/REP.II]

L. A. RASHID, Dy. Chief Controller

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1977

कां था० 3305.—पेट्रोलियम और अधिकारी पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा (2), खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1 में दिये हुए प्राधिकारी के कथित अधिनियम के अधीन अनुसूची के कालम 2 के अनुसूचि लिखित भेज्यों के अन्वर समान प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

प्राधिकारी प्रोर पता

भेज

(1)

(2)

सम्पर्क अधिकारी तेल सम्बन्ध प्राचुर्यक गैस आयोग, महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र सरकार गजन्व तथा यन विभाग, बम्बई

400032

[संख्या 12017/1/74-एल एड एस/प्रोडक्शन]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 26th September 1977

S.O. 3305.—In pursuance of clause (1) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the functions of the competent authority under the said Act within the areas mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Authority and Address	Area
Liaison Officer, Oil and Natural Gas Commission, Government of Maharashtra, Revenue and Forests Department, Bombay-400032.	State of Maharashtra.

[No. 12017/1/74-L&L/Prod.]

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1977

का० आ० 3306.—पेट्रोलियम और अनिंज पाइप लाइन (भूमि के अपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (2), खण्ड (क) के अनुसरण में और भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की विनांक 22 जनवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या का० आ० 389 का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में दिये हुए प्राधिकारी के कार्यत अधिनियम के प्रधीन अनुसूची के कालम (2) में प्रविष्ट के अनुरूप लिखित क्षेत्रों के अन्दर मध्यम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

प्राधिकारी और पता	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)

कामिक तथा प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा इंडियन पेट्रोलियम बंगल
आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरीज तथा
पाइप लाइन प्रभाग) कलकत्ता-700020

[मंख्या 12017/1/74-एल एण्ड एल/प्रोडक्शन]

New Delhi, the 28th September 1977

S.O. 3306.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals No. S.O. 389 dated the 22nd January, 1972, the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the functions of the competent authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Authority and Address	Areas
Personnel & Admin. Officer, C/o. Indian Oil Corporation Ltd. (Refineries and Pipelines Division) Calcutta-700020.	West Bengal

[No. 12017/1/74-L & L/Prod.]

गुदि-पत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

का० आ० 3307.—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के का० आ० सं० 664 के अन्तर्गत अधिसूचना 12020/1/77-प्रोडक्शन-1, दिनांक 31-1-77 जो धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तहसील मधुआ जिला मवाई माधोपुर की उम अधिसूचना से पावड़ अनुसूची में विण्ठन भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिये भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 26-2-77 में पृष्ठ 562 से 565 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में “पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार पर अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50)” शब्दों के स्थान पर “पेट्रोलियम और अनिंज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) शब्द पढ़े जायेंगे।

[क्रमांक 12020/1/77-प्रोडक्शन-1]

CORRIGENDA

New Delhi, the 29th September, 1977

S.O. 3307.—In para 3 of the Government of India Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/1/77/Prod. I dated 31-1-1977 issued under S.O. 664 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos. 832 to 835 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Mahwa District Sawai Madhopur specified in the schedule appended to that Notification, for the words “Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” the words “Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” shall be substituted.

[क्रमांक 12020/1/77-Prod.-I]

गुदि-पत्र

का० आ० 3308.—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के का० आ० सं० 665 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/1/77-प्रोडक्शन-II दिनांक 31-1-77 जो धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तहसील टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर की उम अधिसूचना से पावड़ अनुसूची में विण्ठन भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिये भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 26-2-77 में पृष्ठ 835 से 838 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में “पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)” शब्दों के स्थान पर “पेट्रोलियम और अनिंज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)” शब्द पढ़े जायेंगे।

[क्रमांक 12020/1/77-प्रोडक्शन-II]

CORRIGENDA

S.O. 3308.—In para 3 of the Government of India Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/1/77-Prod-II dated 31-1-1977 issued under S.O. 665 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos 835 to 838 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Todabhim District Sawai Madhopur specified in the schedule appended to that Notification, for the words “Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” the words “Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” shall be substituted.

[क्रमांक 12020/1/77-Prod.-II]

गुरुदि पत्र

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977

का० आ० 3309.—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के का०आ० सं० 662 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/2/77-प्रोडक्शन-II दिनांक 28-1-77 जो धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तहसील मालपुरा जिला टोंक की उम्मीद से पावड़ प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार अर्जित करने के लिये भारत सरकार के राजपत्र भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) विनांक 26-2-77 में पृष्ठ संख्या 822 से 831 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में “पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)” शब्दों के स्थान पर “पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)” शब्द पढ़ें जावेंगे।

[क्रमांक 12020/2/77-प्रोडक्शन 1]

New Delhi, the 1st October, 1977

CORRIGENDA

S.O. 3309.—In para 3 of the Government of India, Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/2/77-Prod-II dated 28-1-1977 issued under S.O. 662 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos 822 to 831 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Malpura District Tonk specified in the schedule appended to that Notification, for the words “Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” the words “Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” shall be substituted.

[No. 12020/2/77-Prod. I]

गुरुदि पत्र

का० आ० 3310.—भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के का०आ० सं० 661 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12020/2/77-प्रोडक्शन-I विनांक 28-1-77 जो धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तहसील मथुरा जिला मथुरा की उम्मीद से पावड़ प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार अर्जित करने के लिये भारत सरकार के राजपत्र भाग-II-खंड 3, उप-खंड (ii) विनांक 26-2-77 में पृष्ठ संख्या 819 से 822 पर प्रकाशित हुई है, के पैरा 3 में “पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)” शब्दों के स्थान पर “पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)” शब्द पढ़ें जावेंगे।

[क्रमांक 12020/2/77-प्रोडक्शन-II]

टी० पी० सुब्रह्मण्यन, अवकर सचिव

CORRIGENDA

S.O. 3310.—In para 3 of the Government of India, Ministry of Petroleum, New Delhi Notification No. 12020/2/77-Prod. I dated 28-1-1977 issued under S.O. 661 and published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) dated 26-2-1977 at page Nos. 819 to 822 under Sub-Section (1) of Section 3 for acquisition of right of user in lands of Tehsil Mathura District Mathura specified in the schedule appended to that Notification, for the words “Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” the words “Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)” shall be substituted.

[No. 12020/2/77-Prod. II]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

का० आ० 3311.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (प्रयोक्ता के भूमि प्रधिप्रण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के बीरभगाम तेल और में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेष्टन स्थित स० एम०पी०ज० से एन०क०ज० से एम०पी०ई० तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के प्रधिकार प्राप्त किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उप-खंड (1) की धारा (1) में निविष्ट कार्य दिनांक 23-2-76 से समाप्त कर दिया गया है।

प्रतः यद्य पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोक्ता के भूमि प्रधिप्रण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत मकाम प्रधिकारी एनद्वारा उक्त तिथि को कार्य सभा की नियम अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एम०पी०ज० में एन०क०ज० से एम०पी०ई० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ०	भारत के	कार्य की
		सं०	राजपत्र में	समाप्ति की
			प्रकाशन की	तिथि
पेट्रोलियम	बालमासण	960	26-3-77	23-2-76
	प्रौद भराराया			

[संख्या 12020/5/77-प्रोडक्शन-I]

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3311.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the Schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. No. SPJ to NKO to SPE in Viramgam Oil field in Gujarat State.

And whereas the oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-2-76

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SPJ to NKO to SPE

Name of Village	S.O.No.	Date of Publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum Balsasara & Bhateria	960	26-3-77	23-2-76

[No. 12020/5/77-Prod. I]

का० आ० 3312.—भारत सरकार के अधिकारियम के द्वारा जैसा कि यहां संस्करण अनुसूची में प्रतिशित किया गया है और पेट्रोलियम और अनिज पाइप लाइन (प्रयोगता के भूमि अधिग्रहण प्रधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात गवर्नर के मेहसाना नेल थोक में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेष्टन स्प्लन में एस०डी०प्रा० २०७ से आर०प्र०य० २०७ से जी०जी०ए० १ तक पेट्रोलियम के लिये भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गये हैं।

तेव एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के लाई 7 के उपर्युक्त (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26-11-75 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम और अनिज पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोगता के भूमि अधिग्रहण प्रधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी एवं द्वारा उक्त नियम को कार्य सम्भा की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुच्छेदी

एस०डी०प्रा० २०७ से आर०प्र०य० २०७ से जी०जी०ए० १ तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गाव	का० आ० में० भारत के राजन्यार्थ समाजिक पक्ष में प्रकाशन की तिथि की नियम
पेट्रोलियम	पुनराम	1893 11-6-77 26-11-75

[संख्या 12020/5/77-प्रोडक्शन-II]

के० श० देशपांडे, गुजरात के लिये नियमान्तरण सक्षम प्रधिकारी

S.O. 3312.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. No. SDR to ROU 207 to GGS-I in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act on 26-11-75.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. SDR to ROU 207 GGS-I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Punisan	1893	11-6-77	26-11-75

[No. 12020/5/77-Prod. II]

K. V. DESHPANDE, Competent Authority Under the Act for Gujarat

उद्घोष मंत्रालय

(वौद्धोगिक विकास विभाग)

नई विल्सनी, 13 अक्टूबर, 1977

का० आ० 3313.—गरकारी स्थान (प्राप्तिवक्तु अधिभोगियों की वेदवाली) अधिनियम, 1971 (1971 का 10) की धारा, 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारीयों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय मरकार नीति की मारणी के सम्बन्ध—1 में वर्णित प्रधिकारी को, जो सरकार का गत्रपक्षित प्रधिकारी है, उक्त प्रधिनियम के प्रयोगता के लिए, सम्पदा प्रधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त मारणी के सम्बन्ध (2) में की सम्बंधी प्रविष्टि में विनिविष्ट मरकारी स्थानों की बाबत, अपनी प्रधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त प्रधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा प्रधिकारी को प्रदत्त अधिकारीयों का प्रयोग और प्रधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

प्रधिकारी का पवारिमिता

सरकारी स्थानों का प्रयोग और प्रधिकारिता की स्थानीय सीमाएं

महायक कलेक्टर, प्रथम थेणी, मंसव मार्ग, नई विल्सनी

दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई विल्सनी के स्वामित्वाधीन/के द्वारा प्रजिन या किराये पर लिए गए सरकारी स्थान।

[का० सं० 29(4)/77-एस आई (2)]

के० एस० बावा, अव० समिति

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 13th October, 1977

S.O. 3313.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in Column-I of the Table below, being Gazetted Officer of Government to be estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table :—

TABLE

Designation of Officer	Category of public premises and local limits of jurisdiction
Assistant Collector, First Grade, Parliament Street, New Delhi.	Public premises owned/acquired or hired by the Delhi State Industrial Development Corporation Ltd., New Delhi.

[F. No. 29(4)/77-SSI(I)]

D. S. BAWA, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1977

का० ग्रा० 3314.—गणनियक एवं कोसली अधिकारी (गणन पूलक) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा (क) व्यवहार (2) के प्रत्यावरण में केवल सरकार इसके द्वारा भारत का राजदूतावाम देहरीन में सहायक, श्री महेन्द्र कुमार को तत्काल से कोसली अधिकारी का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

[फाइल स० टी० 4330/1/77]

एस० एन० गोयल, अवार सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th September, 1977

S.O. 3314.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorizes Shri Mohinder Kumar, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330/1/77]

S. N. GOEL, Under Secy.

नागरीक पूरीं तथा सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

का० ग्रा० 701(अ) 3315.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि दालों और आने योग्य तेलों की मप्लाई बनाए रखने तथा उनका साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और सम्भवीय है;

प्रत, अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल और आने योग्य तेल (प्रणालण नियंत्रण) आदेश, 1977 है।

(2) इसका विस्तार गम्भीर भारत में है।

(3) इस आदेश के खंड 3 और 5, 10 अक्टूबर, 1977 को प्रवृत्त हो जाएंगे और ऐसे उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. परिभासाएः—इस आदेश में, जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अन्येकता न हो—

(क) “व्यवहारी” से वह व्यक्ति अधिग्रहित है जो किसी भी दाल या आने योग्य तेल की खरीद, बिक्री या विक्रयार्थी प्रणालण के कारबाह में लगा हुआ है;

(ख) “उत्पादक” से वह व्यक्ति अधिग्रहित है जो दालों की दलाई के अथवा किसी आने योग्य तेल को निकालने या उसके निष्कासन के कारबाह में लगा हुआ है;

(ग) “दाल” से अधिग्रहित है, उड़द, मूँग, अरहर, मसूर, लोविया, राजमाह या अन्य कोई दाल जो वह पूरी पूरी हो या भूसी नहिं या भूसी रहित दूरी हुई हो;

(घ) “कुटकर व्यापारी” से ऐसी दालों या आने योग्य तेलों का ऐसा व्यवहारी अधिग्रहित है जो थोक विक्रेता न हों;

(क) “राज्य आदेश” से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम सरकार या मध्य ग्राम थोक के प्रशासन द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश जो वनस्पति प्रवृत्त है, अधिग्रहित है;

(च) “थोक विक्रेता” से दालों या आने योग्य तेलों का ऐसा व्यवहारी अधिग्रहित है जो इन वस्तुओं को अन्य व्यवहारियों अथवा बड़ी मात्रा में व्यवहारी दालों या आने योग्य तेलों के हाथ में बेचता है।

3. व्यवहारियों का अनुशासन—किसी राज्य आदेश में किसी आदेश के होने हुए भी, इस खंड के प्रवृत्त होने से पन्द्रह दिन की अवधि के समान हो जाने के पश्चात्, कोई भी व्यक्ति दालों या आने योग्य तेलों में अवधारी के रूप में कोई कारबाह, मिलाएँ, किसी राज्य आदेश के अधीन ही गई अनजान के विवरणों द्वारा दालों के अद्योती और उनके प्रनुसार कारबाह करन के, नहीं करेगा यदि उसके पास दालों या आने योग्य तेलों का ग्राम नीचे विनियिष्ट माला से अधिक हो।

स्टाक की सीमा

(i) दालें सभी दालें, कुल मिलाकर 5 किलोटल।
(ii) आने योग्य तेल जिसमें वनस्पति सभी आने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति भी है, कुल मिलाकर 5 किलोटल।

4. दालें और आने योग्य तेल अपने पास रखने पर नियन्त्रण:—कोई भी व्यवहारी नीचे विनियिष्ट माला से अधिक दालें या आने योग्य तेल का स्वयं या अपनी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी समय, इस खंड के प्रवृत्त होने से पन्द्रह दिन की अवधि के पश्चात्, न तो प्रणालण करेगा और न ही उसे अपने कब्जे में रखेगा।

विवरणों में स्टाक सीमा

थोक विक्रेता	फुटकर विक्रेता
(i) दालें . . . 500 (सभी दालें कुल मिलाकर)	25 (सभी दालें कुल मिलाकर)
(ii) आने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति भी है। 150 (केवल वनस्पति) 5 200 (सभी आने योग्य तेल, जिसमें वनस्पति नहीं है, कुल मिलाकर)	5 (केवल वनस्पति) 5 नहीं है, कुल मिलाकर)

5. विवरणीय—खंड 3 में नियिष्ट प्रत्येक व्यवहारी और प्रत्येक उत्पादक जिसके पास खंड 4 में थोक विक्रेता के लिए विनियिष्ट सीमा से अधिक दालों या आने योग्य तेलों का स्टाक है, दालों और आने योग्य तेलों, जिसमें वनस्पति भी है, के स्टाकों के सम्बन्ध में जो उसके पास है, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी ग्राम से पाधिक विवरणीय भेजेगा जिसे राज्य सरकार इस नियमित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियिष्ट करे।

6. राज्य आदेशों का लागू न होना:—किसी दालों या आने योग्य तेलों के अन्यान्य सम्बन्धी किसी भी राज्य आदेश के उपबन्ध ऐसे किसी भाग में लागू नहीं होंगे जिसके लिए इस आदेश में विनियिष्ट रूप में उपबन्ध किया गया है।

7. आदेश का कुछ मामलों में लागू न होना—इस आदेश की कोई भी वात—

(i) ऐसे नियम या कम्पनी को लागू नहीं होगी जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, अथवा;

(ii) ऐसी किसी केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर की सहकारी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो बालों या बालों योग्य तेलों के उत्पादन, उपापन, विक्रय, खरीद या वितरण में लगी हुई है।

टिप्पणी इस आदेश का अपेक्षी अनुबाद भारत राजपत्र प्रसाधारण, भाग 2, लाल 3 (ii) विनाक 30 सितम्बर, 1977 में छप चुका है।

[फा० सं० 26 (16)/77-ई सी भार]

आदेश

का०आ० 702(अ)/3316.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सरसों के तेल के साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपायेता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1 सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ —(1) इस आदेश का सक्षिप्त नाम सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त हो जायगा।

2 परिभाषा.—इस आदेश में, “व्यवहारी” से ऐसा व्यक्ति प्रभिन्न है जो सरसों के तेल की खरीद, बिक्री या बिक्री के लिए भण्डारण के कारबाह में लगा हुआ है।

3. यह कीमत जिस पर व्यवहारी बेच सकेगा—कोई भी व्यवहारी सरसों के तेल को इस रूपये प्रति किलोग्राम की फुटकर कीमत से, जिसमें साधारण की कीमत शामिल नहीं है, किन्तु कर सम्मिलित है, अधिक कीमत पर, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, न तो बेचेगा और न बेचने की प्रस्थापना करेगा।

टिप्पणी:—इस आदेश का अपेक्षी अनुबाद, भारत राजपत्र प्रसाधारण, भाग 2, लाल 3 (ii), विनाक 30 सितम्बर, 1977 में छप चुका है।

[फा० सं० 26 (16)/77-ई सी भार]

टी० बालकृष्णन, समूक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

का०आ० 3317.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उपरियम (1) के माध्य पठित नियम 8 के उपरियम (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद एलद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को एक नियम, 1969 से 8 मिस्रम्बर, 1977 तक उक्त बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है—

1. श्री बी० जी० कोषी

2. श्री एम० के० वर्मा

[फा० सं० 11/3/76-एफ० सी०]

ए० बी० नारायणन, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3317.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and Sub-rule (3) of Rule 8 1958 with Sub-rule (1) of Rule 7 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory panel of the said Board at Bombay with effect from 1st September, 1977 upto 8th September, 1977:—

1. Shri B G. Koshy.
2. Shri M.K. Verma.

[F. No. 11/3/76-FC]

A.V. NARAYANAN, Dy. Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

बंदोबस्ति विंग

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1977

का०आ० 3318.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की अपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में कार्य कर रहे बन्दोबस्ति अधिकारी श्री प्रीतम मिह को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रबन्ध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का नियादान करने के लिए प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० ए० 36016/1/75-प्रशा० (राज०)/व० वि०]

एच० के० टेकचन्दानी, भवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

SETTLEMENT WING

New Delhi, the 17th September, 1977

S.O. 3318.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (No. 44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Pritam Singh, Settlement Officer in the Department of Rehabilitation, as Managing Officer for the purpose of performing the functions assigned to such Officer by or under the said Act.

[No. A-36016(1)/75-AGZ/SW]

H. K. TECKCHANDANI, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

का०आ० 3319.—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीरा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1969 में कठिपय और समोद्धन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में घोषित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों

की जामकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राप्ति पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालित दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपर विनिविष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्राप्ति की जावन जो भी आधेप या सुमाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेंगे।

नियमों का प्राप्ति

1. इन नियमों का नाम जीर्ण श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1977 है।

2. जीर्ण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1969 में, अनुमूली 2 में, स्तर 1 में, शम संख्या 4 और उसमें सम्बन्धित प्रतिविटियों के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्या, प्रविष्टि और टिप्पण अनुस्पापित किया जाएगा, प्रथम—

“5 अविनिविष्ट श्रेणी, जैसा कि क्रेता और निर्यातकर्ता के भव्य करार हुआ।

टिप्पण—प्रविष्टि श्रेणी के अधीन जीरे का नियति, किसी विदेशी क्रेता के किसी पक्के आदेश प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहने हुए होगा जिसमें जीरे की अपेक्षित क्वालिटी और मात्रा उपर्युक्त होगी और जो उस जीरे के मूल्य के संदर्भ की भी गारंटी देगा।”

[स० फ० 13-1/77-ए०एम०]

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 30th September, 1977

S.O. 3319.—The following draft of certain rules further to amend the Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1969, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Cumin Seeds Grading and Marking (Amendment) Rules, 1977.

2 In the Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1969, in Schedule II, in column 1, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number entry and note shall be inserted, namely:—

“5. Non-specified Grade: As agreed between buyer and exporter.

Note.—Export of Cumin Seeds under non-specified grade shall be subject to the production of a firm order from a foreign buyer which shall indicate the quality, and the quantity required, of the Cumin Seeds, and shall also guarantee the payment of the price of the Cumin Seeds.”

[No. F. 13-1/77-AM]

S.O. 3320.—मधु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए कलिप्य नियमों का एक प्राप्ति, कृषि उप

(श्रेणीकरण और चिह्नांकन) प्रधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की प्रवेशानुसार भारत सरकार के कृषि और सिवाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1399 तारीख 1 अप्रैल 1976 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र धारा 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 17 अप्रैल, 1976, पृष्ठ 1495-1496 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उग तारीख से, जिसको उग राजपत्र की प्रतिया, जिसमें यह प्रधिसूचना प्रकाशित की गई थी, पैतालित दिन की अवधि की समाप्ति तक, उन सभी व्यक्तियों से आधेप और सुमाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

ग्रीष्म उक्त राजपत्र 17 अप्रैल, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

ग्रीष्म केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त आधेपों और सुमावों पर विचार कर दिया है।

ग्रीष्म, ग्रन्त, ग्रन्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त ग्रन्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथम—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मधु श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होने।

2 मधु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1970 में—

(1) नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, प्रथमतः—

(2) श्रेणी अधिकान चिन्ह के अन्तर्गत, भारत सरकार के कृषि विषयन मनाहकार द्वारा निवेशन रीति से निम्नलिखित विशिष्टियां आँकड़ा पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाएंगी, प्रथमतः—

(क) वेकर का नाम

(ख) जिस लाट का वह मधु है, उसकी संख्या

(ग) पैकिंग की तारीख और स्थान

(घ) शुद्ध भार

(ङ) समाप्ति की तारीख

(2) अनुमूली 1 में,—

(क) श्रेणी अधिकान “श्रेणी क” के मामने, स्तर 5 में, प्रविष्टि “8” के स्थान पर प्रविष्टि “5” रखी जाएगी।

(ख) श्रेणी अधिकान मानक के मामने,—

(i) स्तर 5 में, प्रविष्टि “10” के स्थान पर, प्रविष्टि “5” रखी जाएगी।

(ii) स्तर 8 में, प्रविष्टि “60” के स्थान पर प्रविष्टि “65” रखी जाएगी।

[स० फ० 13-10/75-ए०एम०]

प० के० अग्रवाल, उप सचिव

S.O. 3320.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Honey Grading and Marking Rules, 1970 was published as required by the section 3 of Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 1495-1496 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th April, 1976, with the notification of Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development), No. S.O. 1399, dated the 1st April, 1976 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th April, 1976;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

- (1) These rules may be called Honey Grading and Marking (Amendment) Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Honey Grading and Marking Rules, 1970.—

(i) in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly marked on the container in a manner directed by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, namely :—

- (a) Name of the packer ;
- (b) Lot number to which honey pertains;
- (c) Date and Place of packing ;
- (d) Net weight ;
- (e) Date of expiry.”

(ii) in Schedule I,—

(a) against grade designation 'Grade A', in column 5, for the entry '8', the entry '5' shall be substituted;

(b) against grade designation 'Standard',--

(i) in column 5, for entry "10", the entry "5" shall be substituted;

(ii) in column 8, for the entry "60", the entry "65" shall be substituted.

[No. F. 13-10/75-A.M.]

A. K. AGARWAL, Dy. Secy.

नावहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 मितम्ब, 1977

व्यापार पोत

कांगड़ा ३३२।—राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, १९६३ के नियम ३ और ४ के भाव पठिन वाणिज्य पोत अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४४) की धारा २१८ की उप-धारा (१) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं डॉग्डा। राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के निये राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड का गठन करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते, अप्रौद्योगिक विद्युति

1. सौवर्जन-प्रभारी मंत्री (पदेन)	अध्यक्ष
मदस्य	
2. नौवर्जन महानिदेशक, बालसंबंधीयगा०	मदस्य (पदेन)
चंद मार्ग, जहाज भवन बर्बद्द- 10001	
3. संयुक्त मन्त्रिव (नाविक कल्याण), नौवर्जन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली ।	
4. सदायक वित्तीय गलाहकार, नौवर्जन और परिवहन संबालय, विन मंत्रालय (अय विभाग) का प्रभिन्निशि ।	केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि
5. श्री अमो नारायण, उप मन्त्रिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।	
6. श्री एम० धीनिवासन, उप मन्त्रिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परि- वार कल्याण मंबालय, नई दिल्ली ।	

7. श्री आर० के० मुधभट्टी, पतन निर्दे० गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ।
साक, सांनिंविभाग, गांधीनगर ।

8. कप्तान पी० के० प्रार० नव्यर, पतन केरल सरकार के प्रतिनिधि ।
निवेशक, केरल राज्य, त्रिवेशम ।

9. मुख्य पतन अधिकारी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ।
राज्य, बंबई ।

10. कप्तान के० के० एस० कुमारन, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ।
पतन एवं अन्वेशीय जल परिवहन
निवेशक, कारवाड ।

11. श्री पी० एन० बनारा, निवेशक, कलकत्ता पतन न्यास के
जल विभाग, कलकत्ता पतन न्यास, प्रतिनिधि ।
कलकत्ता ।

12. श्री एम० के० जार्ज, बंदरगाह मास्टर, कोचीन पतन न्यास के
कोचीन पतन न्यास, कोचीन । प्रतिनिधि ।

13. कप्तान पी० बलराम, उप संरक्षक, मद्रास पतन न्यास के प्रतिनिधि ।
मद्रास पतन न्यास, मद्रास ।

14. कप्तान पी० डी० गुप्ता, उप संरक्षक, विशाखापत्नम पतन न्यास के
विशाखापत्नम पोटे ट्रस्ट, विशाखा- प्रतिनिधि ।
पतनम ।

15. कप्तान आर० डी० कोल्हारी, कार्यकारी निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लि० शिपिंग हाउस, मेडल कामा रोड, बंबई-400021 ।

16. कप्तान बी० डी० कटारिया, निवेशक, मैसर सैंविन थीम ट्रासपोर्टेशन लि० 15-ए, चन्द्रमुखी, नरीनन पाईट, बंबई- ।

17. श्री टी० एस० नरायन, उप प्रबंधक, मैसरी सिधिया स्टीम नेवीमेशन कंपनी लि० सिधिया हाउस, बंबई-400001 ।

18. श्री एन० लतीक, अध्यक्ष, स्वामियों या एजेंटों की समिति (कर्मीदल) 4-शर्जी बल्लभास मार्ग, बैलाई प्रस्ट, बंबई- ।

19. श्री एन० के० सेन, अध्यक्ष, कलकत्ता लाहौर सम्मेलन (कर्मीदल) 16, स्ट्रीट रोड, कलकत्ता ।

20. श्री के० पी० कोलाह, महासचिव, मेरीटाइम यूनियन आफ इंडिया, नेशनल हाउसरेस विलिंग, 204 डा० डी०एन०रोड, बंबई-400001 ।

21. श्री लियू आन्देस, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ, 1, गोप्ता स्ट्रीट, कोटे, बंबई ।

22. श्री याकूब एम० सेरांग, मारफत भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ, 4-गोप्ता स्ट्रीट, कोटे, बंबई ।

23. श्री नरेण चन्द्र भारद्वाज, मारफत भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ, 10/2-बी, कवितोर्थ मारनी, कलकत्ता-23 ।

24. श्री विलाम मांजरेकर, महासचिव, जहाजी मजदूर यूनियन, कामगार मवन, नवाब ईक रोड, मजगांव, बंबई-4000101 ।

25. श्री डी०पी० कादम । मंसद स्वस्य (लोक सभा)

26. श्री पी० थागराजन ।

27. श्री सुखदेव प्रसाद संसद सदस्य (राज्य मंत्री)
 28. श्री मस्तान मिह, अवैनानिक सचिव, भारतीय नाविक गृह समिति, मस्तिष्क बन्दर, मार्गाड़ग रोड, बंबई-9। नाविकों के कल्याण में रुचि रखने वाली सोमाइया के प्रतिनिधि।

29. श्री के० वी० सुगवानेश्वरन, मस्तिष्क, नाविक गृह समिति, नाविक कल्याण कायानिय, मरीन हाउस, कलकत्ता-22।

30. उप-महानिवेशक नौवहन, नाविक सदस्य सचिव कल्याण के प्रभारी (पद्धेन)

31. श्री के० खाडिलकर, ग्रानात्य भवन, डॉ. गांधीरोड, पारसी कालोनी, दादर, बंबई-14। गैर-सरकारी सदस्य

32. श्री के० वी० अगदीण, 308, थम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001।

33. कप्तान वी० एल० बता, माल अधीक्षक भारतीय मास्टर नाविक कंपनी सिधिया स्थीम नवीगेशन कंपनी लि० के प्रतिनिधि सिधिया हाउस, बंबई।

[एफ नं० एम डब्लू एस (72)/76—एम० ई०]
 श्रीमती वी० निम्न, भवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 29th September, 1977

MERCHANT SHIPPING

S.O. 3321.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 218 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with Rules 3 and 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, the Central Government hereby constitutes, for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the National Welfare Board for Seafarers, consisting of the following members namely :—

CHAIRMAN

1. The Minister incharge of (Ex-officio) Shipping

MEMBERS

2. The Director General of Shipping, 'Jahaz Bhavan', Walchand Hirachand Marg, Bombay-400001. Member (ex-officio)

3. Joint Secretary dealing with Seamen's Welfare, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi.

4. Assistant Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport-representative of the Ministry of Finance (Department of Expenditure).

5. Shri Ashok Narain, Deputy Secretary, Ministry of Labour, New Delhi.

6. Shri S. Srinivasan, Deputy Secretary in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

7. Shri R.K. Bhudhbhatti, Director of Ports, P.W. Department, Gandhinagar.

8. Captain P.K.R. Nair, Director of Ports, Kerala State, Trivandrum.

Representatives of the Central Government

9. Chief Ports Officer, Maharashtra State, Bombay Representative of the Government of Maharashtra.

10. Captain K.K.S. Kumaran, Director of Ports and Inland Water Transport, Karwar. Representative of the Government of Karnataka.

11. Shri P. N. Batra, Director, Marine Department, Calcutta Port Trust, Calcutta. Representative of the Calcutta Port Trust.

12. Shri M. K. George, Harbour Master, Cochin Port Trust, Cochin. Representative of the Cochin Port Trust.

13. Captain P. Balaram, Deputy Conservator, Madras Port Trust, Madras. Representative of the Madras Port Trust.

14. Captain P. D. Gupta, Deputy Conservator, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam. Representative of the Visakhapatnam Port Trust.

15. Captain R.D. Kohli, Executive Director, Shipping Corporation of India Limited, Shipping House, Madam Cama Road, Bombay-400021.

16. Captain B.D. Kataria, Director, Messers Seven Seas Transportation Limited, 15-A, Chander Mukhi, Nariman Point, Bombay.

17. Shri T.S. Narayan, Deputy Manager, Messers Scindia Steam Navigation Company Limited, Scindia House, Bombay-400001. Representatives of Ship-owners.

18. Shri N. Latif, Chairman, Owners or Agents Committee (Crews), 4, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Bombay.

19. Shri N. K. Sen, Chairman, Calcutta Liners' Conference (Crews), 16, Strand Road, Calcutta.

20. Shri K. P. Kolah, General Secretary, Maritime Union of India, National Insurance Building, 204, Dr. D.N. Road, Bombay-400001.

21. Shri Leo Barnes, General Secretary, National Union of Seafarers of India, 4, Goa Street, Fort, Bombay.

22. Shri Yakub M. Serang, care of National Union of Seafarers of India, 4, Goa Street, Fort, Bombay. Representatives of Seafarers

23. Shri Naresh Chandra Bharadwaj, Care of National Union of Seamen of India, 10/2-B, Kabitirtha Sarani, Calcutta-23.

24. Shri Vilas Manrekar, General Secretary, Jhahazi Mazdoor Union, Kamgar Sadan, Nawab Tank Road, Mazagaon, Bombay-400010.

25. Shri B.P. Kadam

26. Shri P. Thiagarajan

27. Shri Sukhdev Prasad Member of Parliament, House of the People (Lok Sabha)

28. Shri Mastan Singh, Honorary Secretary, Indian Sailors Home Society, Masjid Bunder, Siding Road, Bombay-9. Representatives of the Societies interested in the Welfare of Seamen.

29. Shri K. V. Sugavaneswaran, Secretary, Nabik Griha Samity, Seamen's Welfare Office, Marine House, Calcutta-22.

30. Deputy Director General of Shipping, Incharge of Seamen's Welfare (ex-officio).	Member Secretary.
31. Shri K. K. Khadilkar, Anand Bhavan, Dr. Ganti Road, Parsee Colony, Dadar, Bombay-14.	Non-official members.
32. Shri K. B. Jagdish, 308, Thambu Chetty Street, Madras-600001.	
33. Captain B. L. Batra, Cargo Superintendent, Scindia Steam Navigation Company Limited, Scindia House, Bombay.	Representative of the Company of Master Mariners of India.

[F. No. MWS(72)/76-MT]

SMT. B. NIRMAL, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th October, 1977

S.O. 3322.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Loyabad Colliery of M/s Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of
the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 6 of 1977

(Ministry's Order No. L-20012/229/75/DI/PA, Dt. 31-1-1977)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited P. O. Bansjora, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate

For the Workmen—Shri D. Narasingh, Advocate,

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 15th September, 1977

AWARD

By a notice Ext. M-1 (which is the same as Ext. W-1) dated August 30, 1975, the Superintendent, Loyabad Colliery, which is owned by the Bharat Coking Coal Ltd. (hereinafter referred to as the B.C.C.L.), notified Gouri Lohar—the concerned workman—that "As you have attained the age of 60 years we hereby give you a month's notice on expiry of which your services will stand terminated on account of retirement. Accordingly, you will retire on and from 1st October, 1975." This notice was received by Gouri Lohar on September 4, 1975. He protested against his proposed retirement by a letter dated September 5, 1975 and repeated his protest by letter Ext. W-13 dated September 20, 1975 (which was sent by registered post, the acknowledgement being Ext. W-5). In Ext. W-13, he asserted that he had

not attained the superannuation age of 60 years and that he will attain that age in the next 10 to 12 years and, therefore, the notice should be withdrawn and he should be permitted to continue to work as Blacksmith till he reached the age of superannuation. This protest had, however, no effect on the B.C.C.L. and he was superannuated with effect from October 1, 1975.

2. Gouri Lohar represented his case to the A.L.C.. Ext. W-2 contains the comments of the B.C.C.L. on the said representation. It mentions that Gouri Lohar was in the service of the colliery as a Blacksmith since the year 1942; that he had attained the age of superannuation of 60 years, according to the record of his age in the Register Form B; that the year of his birth, as recorded in the register Form B, Stood corroborated by his Service Records and the Identity Card Register maintained by the previous owner; that if he had any complaint against his recorded age, he should not have signed the register form B, and that his contention that he was only 50 years of age at the time of his superannuation was wrong. The conciliation proceedings ended in failure. The dispute thus is whether the action of the management of Loyabad Colliery in superannuating him with effect from 1st October 1975 is justified? If not to what relief is he entitled?

3. It is the admitted case of both parties that the age of superannuation for a Blacksmith, is 60 years.

4. The point in dispute is purely a question of fact. I would first like to comment on the oral evidence in this regard. MW-1 Bansi Bahadur Singh is a clerk in the Welfare Office of the colliery. MW-2 Krishna Mohan is Assistant Personnel Manager, Area No. V, under which area Loyabad Colliery is situated. None of them has any personal knowledge about the date or year of birth of Gouri Lohar. Ordinarily also, they are not expected to have any such personal knowledge. Bansi Bahadur Singh is in the Loyabad Colliery only since 1971 and Krishna Mohan only since 1974. Gouri Lohar is said to have entered service in 1942 and it is obvious that MWS. 1 and 2 can have no personal knowledge about his real age. They have, therefore, rightly based their evidence on documents. WW-1 Gouri Lohar has deposed that he was only 50 years old at the time of his superannuation, and it is wrong that he attained the age of 60 years on October 1, 1975. He is unable to state if he joined service in 1942 or as to what was his age when he started service, and as to whether he was retired after having put in 33 years service. It is again apparent that no reliance can be placed upon his sworn testimony. He is a highly interested witness and knows only this much that he was 50 and not 60 at the time of his superannuation. He does not know the year in which he entered service or his age at that time. He does not know if he was superannuated after 33 years of service. His counsel requested me to look at him while he was present in the Tribunal, and at his photograph Ext. W-12 and form an opinion myself as to his age. Physical appearance, however, is very deceptive. A comparatively young man may look older and a comparatively old man may look younger. Photographs are still more deceptive. It is very risky for a Tribunal to hazard an opinion about age on the basis of its visual observations. The oral evidence, therefore, does not satisfactorily establish that Gouri Lohar was 50 or 60 at the time of his superannuation.

5. When a question of determination of age arises, usually it is established by the production of written admissions of deceased relations, horoscope, birth register, school records, medical certificate supported by reliable oral evidence.

6. The oral evidence has already been noticed above. Gouri Lohar has stated that he signs his name only but was not educated in any school. He has no horoscope and no written admissions of close relations; and has also not filed a copy of the birth register. Indeed, he has not produced any documentary evidence whatsoever in proof of his age, except two which I will now consider. Material Ext. I is a certificate said to have been granted by Dr. B. N. Singh on September 16, 1975 and Material Ext. II is a certificate said to have been given by Dr. S. P. Sinha on October 21, 1975. Gouri Lohar was able to prove his signature only on Material Ext. II. He is illiterate and was unable to prove the two medical certificates. These certificates, therefore, cannot be taken into consideration at all, and more so because the two experts were not examined as witnesses

to afford an opportunity to the B.C.C.L. to test the reliability of the certificates. Thus, there is no documentary evidence to show on behalf of Gouri Lohar that he had not attained the age of 60 years on October 1, 1975 or that he was only 50 years of age at the material time.

7. The B.C.C.L. has relied upon Exts. M-3 and M-4 to prove that Gouri Lohar would have attained the age of 60 years on October 1, 1975. Ext. M-3 is the Register Form B. The name of Gouri Lohar appears at serial No. 776 in this Register. In column No. 4, his age is recorded as the year 1915. The date of commencement of his service, as recorded in col. No. 7, is 1942. This entry is signed by him in Col. No. 7. The contention of the learned counsel for the B.C.C.L. is that this is a statutory register maintained under Sec. 48(1) of the Mines Act read with Rule 77 of the Mines Rules and should carry great weight. MW-2 Krishna Mohan has deposed that Gouri Lohar was superannuated because Ext. M-3 shows that he had reached the age of superannuation. MW-1 Bansh Bahadur Singh has proved this Register. He has deposed that the entry concerning Gouri Lohar is in his handwriting and that the entry was made on the basis of the information given to him by Gouri Lohar and that he signed the entry in his presence. I am not prepared to accept the evidence furnished by Ext. M-3 as conclusive. When the mine was nationalised, there was statutory direction requiring the Custodian to seize all records from the previous owner and I must take it that that statutory requirement was obeyed and fully complied with. That being so, the Register Form B, the Service Records of each workman, and the Identity Register must have been seized and must be in the custody of the B.C.C.L. In a large number of cases, the evidence produced is that after take over, or after nationalisation, the B.C.C.L. prepared a fresh Register Form B. This was done on the basis of the previous Register Form B. It was admitted in Ext. W-2 before the A.L.C. that the Service Records maintained by the previous owner were in the custody of B.C.C.L. The previous Register Form B has not been produced before me, and the new register is usually a copy of the old one with the necessary additions and alterations by adding the names etc. of new hands and deleting the names of those who have gone out of service. Bansh Bahadur Singh admitted that Ext. M-3 was prepared in 1972. He has further admitted that an entry in Register Form B is made when a workman is appointed initially. It appears to me that this must be so because as and when one is appointed initially, his name is bound to be entered in the statutory register Form B giving his name, his father's name, his age, his date of appointment, the nature of his employment etc. etc. These particulars would be ascertained then from the workman who is appointed and not every time that a new register is prepared. Bansh Bahadur Singh joined the Loyabad Colliery in 1971 while Gouri Lohar had joined it more than two decades earlier. I do not understand why Bansh Bahadur Singh would ask him over again about his particulars when all the particulars would be found in the previous register. Besides, even though he asserted that the entire entry is in his own handwriting, that does not appear to be correct because several inks and pens have been used, and the handwritings also appear to be in different hands. WW-1 Gouri Lohar has deposed that the particulars mentioned in Ext. M-3 are signed by him but the contents were never explained to him when the entry was made. He admits the correctness of all the particulars given, except the entry regarding his birth. Ext. M-4 is the Identity Register. I need not give the details of the entry at serial no. 154. It repeats the year of birth as 1915 and the date of employment as 1942. It is not signed by Gouri Lohar. Bansh Bahadur Singh deposed that an identity card containing all the particulars mentioned in Ext. M-4, was issued to Gouri Lohar and his signature was obtained in token of receipt, but when he was confronted with the register, he had to admit that his signature was missing. Gouri Lohar has denied that any identity card was issued to him. I must accept his evidence when the register does not contain his signature acknowledging receipt of the identity card. These are the only two documents on which reliance has been placed. It should have been apparent to the B.C.C.L. that when the notice was issued what was required was its own satisfaction about the age of Gouri Lohar but when that fact was challenged and an industrial dispute has been raised as to what is his age it is my satisfaction which is material. The B.C.C.L. was, therefore, under an obligation to place all the material documents before me, namely, the previous Form B Register of the time of the previous owner the previous service records of Gouri Lohar and any other material docu-

ment to show that its satisfaction was a justified satisfaction. Since those documents have not been filed, I am reluctant to accept Ext. M-3 and M-4 as conclusive on the matter.

8. Ext. M-5 is a circular issued by the Chief, Industrial Relation and Personnel, B.C.C.L., on January 6, 1973. Paragraph 2(v) mentions that "in respect of record of age the same recorded in the P.F. records should be taken as criteria. In case any representation is made against this the same may be examined and settled." This circular regulates the procedure for superannuation. The directive given is that in calculating the age of superannuation, the basic record to be taken into consideration is the P. F. record. However, if the workman challenges the accuracy of that record, then the matter must be examined and settled. Krishna Mohan has deposed that this record was consulted before the notice of superannuation was issued. I have no reason to discard his evidence. He must have consulted the record. However, the age has been challenged by the workman. The B.C.C.L.'s satisfaction, therefore, should have been made my satisfaction also. The P.F. record should have been produced before me to show as to what is the age recorded therein but this has not been done. No attempt has been made to satisfy me on the basis of that record that Gouri Lohar had attained the age of superannuation and no reason is forthcoming as to why that record has not been produced. Again, as soon as Gouri Lohar received the notice, he challenged that he had not attained the age of superannuation. No attempt was made to examine and settle the dispute before October 1, 1975 and he was made to retire automatically on that date. This was not proper. Either six months notice should ordinarily be given so that there is ample time for both parties to arrive at a settlement about the age of, if one month's notice was given, as is the case, then the B.C.C.L. should have settled it by September 30, 1975.

9. It was contended by the B.C.C.L. that repeated offers were made to Gouri Lohar to present himself for examination by an independent Medical Board consisting of Superintendent, Loyabad Central Hospital, one Doctor from Central Government Hospital at Dhanbad and the third Doctor from the District Hospital, Dhanbad but he persistently refused to appear for medical examination. All these offers, however, were made long after retirement. Ext. M-6 shows that such an offer was made on May 5, 1976. Ext. W-4 is another offer dated July 10, 1976. Before the R.L.C. also, the B.C.C.L. made the same offer on December 11, 1976 but Gouri Lohar backed himself out. He has denied that any such offer was made at that stage. But that does not appear to be correct in view of the proceedings. Ext. M-7. MW-2 Krishna Mohan has also deposed that such an offer was made before the R.L.C. but Gouri Lohar did not accept it. He stands supported by Ext. M-7. It is clear, therefore, that B.C.C.L. made an attempt to settle the dispute some months after superannuation by inviting Gouri Lohar to subject himself for examination by a Medical Board but Gouri Lohar declined to do so. It was argued that an inference should, therefore, be drawn that he so declined because he was sure that the verdict would go against him. That inference is a possible inference but is not conclusive. Needless to mention that the evidence of a Medical man, however, eminent, is ordinarily a matter of mere opinion. Human judgment is fallible, and human knowledge is limited and imperfect. Medical evidence as to age is from its very nature based on conjecture and cannot be safely relied on to determine with precision the exact age of a person. True, ossification test may be a more sure test basis than the opinion of a medical expert, but cannot be regarded as conclusive and particularly so when ossification generally stops after a particular age. I do not mean to say that the idea of a Medical Board should be eschewed but it should be given a secondary importance. The main authentic document would be the certified copy of the Birth Register. The birth of every new born is recorded at Police Stations or in Chowkidar's Book etc. A certified copy of Birth Register can be produced and evidence can be taken as to how many sons a particular man had, what their names were, what was their seniority inter se, when they were born, and the various birth certificates will establish their individual dates of birth.

10. There are three reasons why I cannot confirm the order of B.C.C.L. Firstly, because the various documents on the basis of which it reached its satisfaction, have not been produced before me; secondly because, the directive of the Chief, Industrial Relations and Personnel was not followed; and thirdly, the Register Form B only mentions the year of birth as 1915 and not the date of birth, or that it was Octo-

ber 1, 1915. Gouri Lohar might will have been born on 31-12-1915 as that date would also fall within the year 1915. No basis has been given as to how the conclusion was reached that he was born on October 1, 1915.

11. I trust that the most just and proper manner of determining the age of Gouri Lohar would be to direct him—

(a) to file an affidavit mentioning—

(i) the names of his brothers, whether alive or dead, if any.

(ii) their places and his own place of birth, together with particulars in respect of Post Office, Police Station, District and State.

(iii) their, and his own date of birth and year.

(b) to file certified copies of their and his own Birth Register, and

(c) to lead such other oral and documentary evidence, as he may consider necessary, and to connect the Birth Registers with the respective persons whose dates of birth are recorded therein.

12. The Superintendent of the Colliery should show to Gouri (i) Service Records pertaining to him, (ii) the present Register Form B and the Register Form B of the time of the previous owner of the mine and (iii) the P. F. Records maintained at the colliery and certified copy of such record maintained in the P. F. Commissioner's office and (iv) the Identity Register.

13. If necessary, Gouri be required to appear before a Medical Board consisting of one Doctor of the Central Govt, Hospital in Jagjiwan Nagar, one Doctor of the District Hospital, Dhanbad and one Doctor of the Colliery.

14. On the totality of all this evidence, the Superintendent should review his order about the date of superannuation.

15. My award is that Gouri shall file the affidavit mentioned in paragraph 11 before the Superintendent, within one month of the publication of the Award and also comply with clauses (b) and (c) of paragraph 11 within a reasonable time thereafter. The Superintendent shall comply with paragraphs 12, 13 and 14 of the Award. He shall pass his final orders, on the basis of the result of his findings.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

[No. L-20012/229/75-D III A]

New Delhi, the 5th October, 1977

S.O. 3323.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dharma Band Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Malkera, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th September, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 11 of 1976

(Ministry's Order No. L-20012/115/76/DIIIA, dated, 27-10-76)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dharmaband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Malkera, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Narsingh, Advocate, with Shri J. D. Lall, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 24th September, 1977

AWARD

Bisarjan Bhar and Hiyati Mia were both Loaders in the Dharmaband Colliery. The chargesheet Ext. M-1 dated May 7, 1975 was served on Hiyati Mia and the chargesheet Ext. M-14 of even date on Bisarjan Bhar. The charge against both of them was couched in identical terms, namely, that at about 8.30 a.m. on April 25, 1975, they, and a few other workmen, went to the office of C. P. Singh, the Colliery Manager, and without any reason or provocation, started shouting and when C. P. Singh asked them not to shout they dis-obeyed him, and pointing their fingers towards Sadan Singh, the Asstt. Colliery Manager, said : "AAP FALL BACK KEYON NAHIN DENGAY. AAP KO DENA HOGA, AGAR AAP HAMARA FALL BACK KATENGEY TO HAM BHI AAP KA HATH PAIR KAT DENGAY." At this stage, C. P. Singh intervened and made efforts to pacify them but thereupon they again started shouting in loud tones and addressing their co-workers said : "YEH LOG DHANDHLI KARTE HAIN. AB PHIR MAR PEET KARNE KE BINA KAM NAHIN HOGA. CHALO KAL PHIR AKAR JO KUCCH BHI BACHA HAI KARENGE." They were then asked to go out of the office but they did not obey and continued to shout for about half an hour and in that manner they did not allow C. P. Singh to do his normal work. They were, therefore, charged with the commission of the misconducts of wilful insubordination and dis-obedience under Standing Order No. 29(c); riotous, dis-orderly and indecent behaviour under Standing Order No. 29(e); causing wilful damage to work in progress under Standing Order 29(i), threatening their superiors under Standing Order 29(r) and preaching of and inciting violence under Standing Order 29(t).

2. Ext. M-2 and Ext. M-15 dated May 12, 1975 are the replies of Hiyati Mia and Bisarjan Bhar respectively. The replies are identical and are to the effect that the charges against them were false, concocted and motivated to victimise them as they were active members of the Bihar Colliery Kamgar Union and as such eye-sores to the management. They alleged that they had gone to C. P. Singh's office to protest against the unjustified deduction of fall back wages in a democratic and orderly manner but their protest was mis-understood, and the falsity of the charges will further appear from the belated issue of the chargesheets.

3. D. Biswas, the Personnel Officer, was appointed Inquiry Officer. He held separate domestic inquiries against the two workmen. C. P. Singh and Sadan Singh gave their depositions against Hiyati Mia, and Hiyati Mia examined himself and Zahir Mia in his defence. C. P. Singh, Sadan Singh and K. P. Singh gave their depositions in the separate domestic inquiry against Bisarjan Bhar, and Bisarjan Bhar examined himself alone in his defence. D. Biswas submitted his inquiry report Ext. M. 12 against Hiyati Mia on December 26, 1975 and a separate inquiry report Ext. M-32 against Bisarjan Bhar on January 12, 1976. He held that the charges under Standing Orders Nos. 29(c) and 29(i) were not established against either of them but the remaining three charges were fully established against both of them. The colliery Manager

proposed the punishment of dismissal of both the workmen and the same was approved by the General Manager by his order Ext. M-34 dated January 21, 1976. The Colliery Manager then issued the formal order of dismissal Ext. M-3 against Hiyati Mia and Ext. M-33 against Bisarjan Bhar on January 22, 1976, dismissing both of them from January 24, 1976.

4. The learned counsel for the management desired that it be decided as a preliminary matter, as to whether or not the domestic inquiry was fair and proper. That matter was decided on May 30, 1977 and it was held that the two domestic inquiries were not fair and proper. In view of that decision of the Tribunal, both sides have led evidence on merits in the Tribunal itself.

5. There is no controversy between the parties that the questions whether the three charges are established or not and the punishment of dismissal is justified or not, have to be decided on the basis of the evidence taken by the management at the inquiry and the proceedings of the inquiry, and also on the basis of the further evidence led by them before the Tribunal.

6. The management has examined MW-2 C. P. Singh, the Colliery Manager; MW-3 Sadan Singh, the Asstt. Colliery Manager; and MW-4 U. P. Singh, the Colliery Personnel Officer in support of the charges. The workmen have examined themselves—Hiyati Mia as WW-1 and Bisarjan Bhar as WW-2 to controvert the evidence given by the management.

7. C. P. Singh has stated that he was sitting in his office room on April 25, 1975 along with Sadan Singh and U. P. Singh, when, at about 8.30 a.m., Hiyati Mia and Bisarjan Bhar, and a few other workmen, entered the room and Hiyati Mia raised the question of the allotment of a house to him on the ground that till then he had been staying at the house of a friend of his at Malkera Choitubh but had now brought his family also and should, therefore, be provided with an accommodation in the colliery itself. His statement is further to the effect that he informed Hiyati Mia that no accommodation could be provided to him immediately but houses were under construction and as soon as these were ready, allotment will be made and he should take his chance in the queue then. After this talk, Bisarjan Bhar pointed his fingers towards Sadan Singh and raised the question of non-payment of his alleged outstanding fall-back wages. While raising his problem, he told Sadan Singh: "AAP KYON HAMARA FALL BACK NAHIN DENGAY. AAP KO DENA HOGA. AGAR AAP HAMARA FALL BACK KATENGEY TO HAM BHI AAP KA HATH PAIR KAT DENGAY." The witness informed Bisarjan Bhar that a claim for fall-back wages is not met straightforward but has to follow compliance with the procedure. He also told him that the procedure was that he should make an application and his claim will then be considered on merits. At this stage, however, Hiyati Mia also repeated the same words verbatim which had been earlier used by Bisarjan Bhar. The witness told both of them that that was the wrong way to represent their case and it was not going to solve their problem. Bisarjan Bhar then turned towards the witness and said: "AAP BHI BAHUT DHAN-DHLI KARTE HAIN. AB HAM LOGON KO KUCHH KARNA HOGA." Hiyati Mia added to this by saying: "AB BILA MAR PEET KEY KAM NAHIN CHALEGA." The witness then told them that their shouts and threats were not going to solve their problems and they better went out from the room. In spite of this, they stayed for sometime more and kept on shouting. Thereafter, while going away, they said: "AB CHALO AAJ JO KUCHH BACHA HAI KAL DEKHENGAY." The witness has admitted that the claim for fall-back wages related to Bisarjan Bhar only and Hiyati Mia had not put forward any such claim. In cross-examination, he further admitted that neither Hiyati Mia nor Bisarjan Bhar had used any abusive words; nor did any of them assault any of the three officers present in the room, and none of them turned up next day also to execute their threats. He further admitted that at times when temper rises, serious threats are uttered which are never intended to be implemented, but the previous atmosphere of the colliery had been such that even such idle threats could materialise. Sadan Singh has deposed that Hiyati Mia and Bisarjan Bhar, with 20 or 25 others, came into the room, and Hiyati Mia raised the question of the allotment of a house to him. C. P. Singh told Hiyati Mia, that a house cannot be given in 2 or 3 days, that houses were under construction and when these

were ready, one house would be given to him also. Hiyati Mia, however, said that the house must be given that very day; or else he will not leave the room till it was given. The battle was then taken up by Bisarjan Bhar who rolled his red eyes towards the witness and said that he must pay his fall-back wages. He also said: "MSRA FALL BACK WAGES DENA HOGA. KYON NAHIN DEGA. NAHIN DEGA TO AAP KA HATH PAIR KAT DENGAY." Hiyati Mia repeated the same threat. C. P. Singh then told them that that was not the way to make a demand and they should make written applications which would then be considered by him. Upon this, Bisarjan Bhar said: "AAP BHI DHAN-DHLI KARTE HAIN. AISE KAM NAHIN CHALEGA. KUCHH KARNA HOGA." Hiyati Mia repeated these words and said: "PHIR MAR PEET KARNA HOGA. BILA MAR PEET KEY KAM NAHIN CHALEGA." C. P. Singh made efforts to pacify the two by saying that nothing would turn on the basis of the manner of their talk; but his advice had no effect on them. They continued to do "HALLA GULLA" for sometime more. Thereafter they went away saying "AAJ CHALO. JO KUCHH BACHA HAI KAL KARENGEY." His cross-examination shows that the first to talk was Hiyati Mia whose demand was for a house, and the next to talk was Bisarjan Bhar whose protest was for non-payment of his fall-back wages. However, the witness says that Hiyati Mia also supported the demand for fall-back wages. He has denied that any threats were not given. He has also denied that the talk took place in a peaceful manner. U. P. Singh has deposed that Bisarjan Bhar, Hiyati Mia and 20-25 persons came into the room. Hiyati Mia asked C. P. Singh to provide him with an accommodation as his family had arrived. He also represented that he was residing in a rented house at Malkera colliery and he was in fear of danger to his life in coming to the colliery and going to his house after end of shifts in night time. He further told C. P. Singh that only 2 or 3 days earlier, some miscreants had surrounded him and he was, therefore, in great need of a house in the colliery premises itself. C. P. Singh told him that a house cannot be allotted on his mere asking, that houses were under construction and when these were ready he could apply in writing then and his application will be considered on merits. At this stage, Bisarjan Bhar addressed Sadan Singh and asked him why he was refusing to pay him fall-back wages. He further said: "AAP KO DENA HOGA. AGAR AAP FALL BACK KATENGEY TO MAI BHI AAP KA HATH PAIR KAT DOONGA." C. P. Singh told Bisarjan Bhar that no problem can be solved by a talk in that tone and manner. He also told Bisarjan Bhar that he should make a written application, which he (C. P. Singh) will consider on merits. Upon this, Bisarjan Bhar, "AAJ CHALO. PHIR BINA MAR PEET KAM NAHIN CHALEGA." Hiyati Mia addressed Bisarjan Bhar and said: "THEEK HAT AAJ CHALO. JO KUCH BACHA HAI KAL PURA KARENGEY." Then these two and their companions went away shouting. In cross-examination, he denied that they had made their demand only in a peaceful manner and had then dispersed.

7. Hiyati Mia's deposition is that he had gone to C. P. Singh's room to demand the allotment of a house and not for wages. He, however, admitted that in his reply to the charge-sheet, it was mentioned that he had gone to demand the payment of fall-back wages but explained it by saying that the reply was wrong inasmuch as he had no such demand to make and further because, he being illiterate, had handed over the charge-sheet to someone in the union office for drafting his reply and had thereafter returned to his place of work and next day he had merely put his thumb impression on the reply without knowing the contents. This explanation of the witness in the domestic inquiry by the management's witnesses and the evidence given in the Tribunal, goes to show that Hiyati Mia's demand was only for a house and he had no interest in or concerning any fall-back wages and, as a matter of fact, he had raised no such demand also. In view of these admissions, it is obvious that the reply to the charge-sheet was incorrect and his stand is correct that he had gone merely to make a demand for the allotment of a house. He goes on to state that when he demanded the accommodation, C. P. Singh told him that a house will be allotted when those under construction were ready and he would get one when his turn came. He has further deposed that he told C. P. Singh that his family had arrived and he was in need of an accommodation in the colliery premises itself in order to remove the inconvenience caused to him in coming from and going back to Bhelatand, 3 miles away, where he was

then residing. He had denied that he abused C. P. Singh or Sadan Singh. He has denied that he repeated any threats or uttered any on his own. He has then deposed that he was the first to go inside the room and Bisarjan Bhar turned up 8 or 10 minutes later and he went away while Bisarjan Bhar was still present inside the room. In cross-examination, he has denied that he and Bisarjan Bhar had gone to the Manager's room together. He admitted that Bisarjan Bhar had asked Sadan Singh for his fall-back wages. He also admitted that Sadan Singh had told Bisarjan Bhar that he will check the colliery's books of account and if fall-back wages were due these will be paid to him. He says that he went away at this stage of the talk between Sadan Singh and Bisarjan Bhar and does not know what transpired between them after his departure. He has denied that the various threats were uttered by Bisarjan Bhar in his presence. He has also denied that he had repeated these threats or uttered any threats himself. Bisarjan Bhar has deposed that he went alone to the Manager's room to demand his fall-back wages. He found Hiyati Mia present there from before. In his presence, Hiyati Mia did not give any abuses or utter any threats to any officer. Hiyati Mia went away, while he himself continued to be present in the room. He demanded his fall-back wages from Sadan Singh. Sadan Singh told him that he will check the account books to ascertain if the wages were due, and if these were found to be due, payment will be made to him. He quietly went away after that. He has deposed that it is false that he had told Sadan Singh that if his fall-back wages were not paid, he will cut his hands and feet. He has also denied that he had uttered the threat that what remains to be done will be done next day. In cross-examination, he stated that when he reached inside the room, Hiyati Mia was demanding a house for himself. Hiyati Mia was saying that he had his residence at Bhetatand, that his family had arrived, that only 3 or 4 days earlier while he was going to the colliery in the night time some miscreants had attempted to rob him and had actually seized a watch from him and ever since then his life was in danger, and for these reasons he should be provided with a house. The witness says that he did not hear C. P. Singh telling Hiyati Mia that no house was immediately available, that houses were under construction, and one will be provided to him when the houses were ready. He is falsely telling a lie here. He must have heard the manager's reply because he was standing within 3 or 4 paces both of Hiyati Mia and C. P. Singh. In cross-examination, he has further denied that he had told Sadan Singh that his fall-back wages had been wrongly deducted. He has further denied that he had gone to make a protest against unjustified deduction. He was confronted with his reply to the chargesheet which mentions that he had gone to protest against the unjustified deduction, but he says that that reply was wrong and the mistake occurred because he had merely put his thumb impression on it. It is obvious to me that he is telling a lie again. He had made damaging admissions in his statement in the domestic inquiry. He had stated there that "GHARIB KA JO PET KATTA HAI BHAGWAN BHI USKA PET KAT SAKTA HAI". He had stated in the domestic inquiry that it was possible for the management to obtain his thumb impression on the monthly pay-sheet, and then tell him that his wages had been paid. He had also stated that it was possible for the management to engage Goondas and have his feet and hands broken by them. He says that he had not made these statements, but when confronted, he is unable to give any explanations. He has denied that he uttered the various threats suggested to him in cross-examination. He has also denied that Hiyati Mia had repeated any threats.

8. I am not reproducing in detail the statements made by the various witnesses in the domestic inquiry; firstly, because there were two separate inquiries and it will not be proper to read the evidence in the inquiry against Hiyati Mia as evidence against Bisarjan Bhar or vice-versa. Secondly, besides some minor deviations here and there, the evidence in the domestic inquiry and before the Tribunal is practically the same.

9. On a consideration of the totality of the evidence on record, I am of the view that none of the three charges are established against Hiyati Mia. There was no community of interest between him and Bisarjan Bhar. One was in dire need of a house and the other was in an angry mood for

deduction of fall-back wages which he considered to be unjustified. The situation was such that one will go to bescach, to entreat, to make a request for a house and not to quarrel, while the other will go not to request but to protest, as he admitted also in his reply to the chargesheet. He was labouring under a sense of grievance that fall-back wages were due and were not being paid arbitrarily. The management was telling him that he should make an application but he was arguing with the management. At least, he had deposed in his statement in the domestic inquiry that God will stop their ration if his fall-back wages were stopped; and going out of bounds of common courtesy, had said that C. P. Singh could even engage a Goonda and have his hands and feet broken. He had also said that he could even obtain his thumb impression on the wage-sheet and show a false payment. These facts show his mental attitude of insubordination and defiance of authority. It is true that he denies that he had made these statements, but the record is there to see. In his case, I do not see any reason why I should disbelieve the three important and responsible officers that he had uttered the threats attributed to him. So far as Hiyati Mia is concerned, his business was over as soon as his housing difficulty remained unsolved. He would have no reason to stay behind only to pick up a quarrel with the officers with regard to a matter with which he had no concern. No fall-back wages were due to him. He did not make any demand for such wages. These facts are admitted even by the management. Hiyati Mia says that he walked away after his own matter was over, and I see no reason to disbelieve him. The charge mentions that it is he who had demanded fall-back wages, it is he who had uttered the threats, and it is he who had taken an unreasonable attitude. The evidence given is that he made no demand for fall-back wages and he did not utter the threats. Again, the evidence given is that he only repeated the threats. There is a wide gap between the charge and the evidence. I find that the three charges against Bisarjan Bhar were established, namely, he uttered threats to his superior officers, that he preached violence and indulged in disorderly behaviour. None of the charges is, however, established against Hiyati Mia.

10. In the chargesheet, the three misconducts proved against Bisarjan Bhar are mentioned as misconducts under Standing Order No. 29(c), (r) and (t). It was argued that the misconduct of "threat" to superiors under 29(r) and "preaching of or inciting to violence under 29(t) are not misconducts at all under the Standing Order; and "disorderly behaviour" is misconduct under 27(s) and not under Standing Order No. 29 and, therefore, none of the charges can be taken to have been established. The evidence shows that the name of the colliery before nationalisation was Khas Dharmaband colliery. Ext. M-36 is the Standing Order. The misconducts are enumerated in Standing Order No. 27 and not in Standing Order No. 29. Likewise, threatening of superiors and preaching of or inciting to violence are not defined misconducts in Standing Order No. 27. That will, however, not mean that a wrong quoting of the number of the Standing Order will be material; nor will it mean that a workman can be punished only for a defined misconduct. There may be other kinds of behaviour which will invite punishment if such behaviour is detrimental to discipline. The facts constituting misbehaviours were mentioned in the chargesheet. Threatening superior officers and preaching and inciting violence are definitely misbehaviours. That being so, I am of the view that Bisarjan Bhar's dismissal was eminently justified.

11. My award is that the management has failed to establish any charge against Hiyati Mia. He shall be reinstated from January 24, 1976 and shall be paid his full back wages and other monetary benefits. My award further is that Bisarjan Bhar was rightly dismissed and is not entitled to any relief.

K. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-20012/115/76-DHIA]

New Delhi, the 11th October, 1977

S.O. 3324.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Badjna Sub-Area No. VI of M/s C.M.A. Ltd., P.O. Nirsachatti, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 29th September, 1977.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) AT DHANBAD

Reference No. 12 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Badjna Sub-Area number VI of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post office Nirsachatti, District Dhanbad.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 17th September, 1977

AWARD

This is a reference u/s 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 (hereinafter called the Act) by the Central Government Ministry of Labour under order No. L-20012/132/74-LRII/DIIA dated 2-4-75. Schedule of reference is extracted below:

SCHEDULE

"Whether the management of Badjna Sub Area Number VI of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post office Nirsachatti, District Dhanbad, are justified in stopping the work of Sarvashri Jiwan Krishna Mazumder and Shyamal Kumar Roy, General Clerks, Badjna Sub Area office with effect from 25-2-74? If not, to what relief the said workmen are entitled?"

2. The two workmen Shri Jiwan Krishna Mazumder and Shri Shyamal Kumar Roy of Badjna Sub Area M/s. Coal Mines Authority Ltd. (at present Eastern Coalfields Limited) P.O. Nirsachatti District Dhanbad are involved. But in fact we are concerned only with Shri Jiwan Krishna Mazumder. Shri J. D. Lal appearing for the two workmen has submitted that he has no material in his possession to press the case of Shri Shyamal Kumar Roy. Therefore, although in the reference there are two workmen, it is a case of only Shri Jiwan Krishna Mazumder that we are concerned with and with respect to Shri Shyamal Kumar Roy the justifiability of the action of the management is not being challenged.

3. The dispute was sponsored by Bihar Colliery Kamgar Union before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad, when it was complained to him that the management of Badjna Sub Area of Coal Mines Authority Limited had illegally stopped Shri Jiwan Krishna Mazumder and Shri Shyamal Kumar Roy from work. The management was called upon to give its comments which it did on 23-3-74 with a copy to the union.

4. It appears that the union relied upon the agreement dated 27-11-72 in which the workmen in question were detailed as retrenched workmen and were to be given priority in employment. The management, however, took up the stand that it being not a party to the settlement was not bound by it and no list of workmen had ever been given to them from which it could be ascertained if the two concerned workmen were also affected.

5. The matter was discussed on several dates and the Assistant Labour Commissioner also visited the office of the Badjna Sub Area where he inspected some documents to

find out if the concerned workmen had ever worked in the office. It appears that it was only Shri Mazumder who put forward certain papers before him but Shri Shyamal Kumar Roy was conspicuously absent.

6. The conciliation efforts failed as the parties could not arrive at a settlement and the Assistant Labour Commissioner sent a failure report dated 27-9-1974 to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, when the present reference was made.

7. A written statement has been filed on behalf of the employers stating therein that there is no such Sub Area known as Badjna Sub-Area No. VI of M/s. Coal Mines Authority Ltd. and therefore the reference which mentions Badjna Sub Area No. VI is not a competent one and it must be thrown out on that ground alone.

8. It is further said that no dispute much less any industrial dispute was ever raised by the workmen with the employers prior to their approaching the Assistant Labour Commissioner. The present reference which is on the basis of the failure report of the conciliation officer is clearly illegal and unwarranted inasmuch as letter to the conciliation officer by the union a copy of which was sent to the employers by the company can at best be considered a demand and not an industrial dispute between the workmen and the employers. On this ground also the reference is incompetent.

9. It is contended that none of the two workmen was ever employed in the Badjna Sub Area office in any capacity whatsoever and therefore the question of stopping them from work w.e.f. 25-2-74 does not arise.

10. It is also contended that in the course of the conciliation proceeding before the Assistant Labour Commissioner reliance was placed on behalf of the union on a tripartite settlement dated 23-11-72 in which besides other terms it was stipulated that those who would not like to work as miners or trammers would be kept in writing list and their cases would be discussed by the management and the union during the first week of February, 1972 for final settlement. As the Government of India took over the management of Shyampur colliery on 31-1-1973 there was no question of any discussion between the union and the custodian.

11. Case further is that in the memorandum no list of workmen who were affected by the settlement was appended and it was only at later stage that a list was given by the union which was undated and the two concerned workmen were shown to have been employed as Attendance Clerks. But when the records of Shyampur colliery was checked it transpired that they had never worked in that colliery in any capacity nor they were retrenched by the erstwhile owners. Two documents purported to have been written by Shri J. K. Mazumdar were brought before the conciliation officer to prove his alleged connection with the Badjna Sub Area office but they were written in connivance and in collusion with some subordinate staff which cannot bind the employers.

12. It is submitted that the concerned workmen have no case and the reference cannot be answered in their favour.

13. On behalf of the workmen written statement has been filed standing therein that they were working in Shyampur colliery and were permanent workmen of that colliery. Incline No. II of that colliery was closed by the erstwhile management as a result of which 105 workmen working in that incline and other clerks including them were proposed to be retrenched w.e.f. 3.10.72 and the Bihar Colliery Kamgar Union raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad, in regard to the proposed retrenchment of those 105 workmen. At the intervention of the Assistant Labour Commissioner an amicable settlement was arrived at whereby it was agreed to absorb those 105 workmen. By the time the management was taken over by the Central Government 11 of those workmen including these two remained to be absorbed and the union took up their case with the management. After prolonged correspondence and negotiations the two concerned workmen were re-employed by the Coal Mines Authority Ltd. as clerks in Badjna Sub Area Office w.e.f. 10-1-74 and worked till 24-2-74 when suddenly on 25-2-74 they were stopped without assigning any reason.

14. It is contended that the union made several representations to the management but nothing was done and the management was not justified in stopping them without assigning any reason and without proper order in writing. This action is violative of the certified standing orders and also of the principles of natural justice.

15. There is a rejoinder on behalf of the employers contending inter-alia that they relied on the settlement dated 27-11-72 for its true and correct import and whether the two concerned workmen were to be absorbed at all.

16. In other paragraphs of the rejoinder facts mentioned in the written statement have been reiterated and submission has been made that the concerned workmen are entitled to no relief.

17. There is also rejoinder on behalf of the employees. It is said therein that if by mistake Sub Area No. VI had been mentioned in the reference but if both parties are aware that the dispute relates to Badjna Sub Area the reference cannot be said to be incompetent.

18. It is further said that the workmen had raised dispute with the employers before the union raised industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad. Even if no such demand had been raised before the employers, on that ground alone the reference cannot be said to be incompetent.

19. Another point that has been taken is that according to terms of reference the workmen had worked in Badjna Sub Area office and, therefore, the employers are precluded from challenging the same.

20. On behalf of the workmen Shri Mazumder has examined himself. On behalf of the other workmen no documentary evidence has been produced nor he has examined himself. Exts. W-1 and W-2 are the signatures of Shri Mazumder on the dak despatch register, Ext. W-3 to W-3/2 are the letters sent by the Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union to the Deputy Custodian General, General Manager and the Area General Manager, Coal Mines Authority, respectively.

21. So far as the employers are concerned they have examined Shri R. C. Sharma who is now working in Badjna Sub Area and had participated in conciliation proceeding representing the management. Ext. M-1 is a copy of letter dated 24-6-74 from Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union to the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad which was forwarded to the management. Ext. M-2 is a letter dated 29-6-74 from the Assistant Labour Commissioner to the Sub Area Manager asking him to attend for discussion, concerning the above dispute. Ext. M-3 is the attendance register, Ext. M-4 form B register and Ext. M-5 is monthly pay sheet register.

22. At the time of argument besides the two legal objections that have been raised in the written statement of the employers, it has further been contended that the Badjna Sub Area being not a mine as defined in the Mines Act, the two workmen may be workmen u/s 2(s) of the I. D. Act, but the Central Government cannot be considered an appropriate government as defined in S. 2(a) of the Act and any reference made by it concerning the two employees of Badjna Sub Area Office is undoubtedly incompetent and this Tribunal is also not competent to entertain this reference.

23. Before taking up the facts involved in the case I would like to dispose of the law point first. So far as the above argument is concerned I find that there is a good deal of substance in it. The term 'mine' has been defined in S. 2(j) of the Mines Act and in S. 2(h) of that Act who would be considered to be employed in a mine has been elaborately defined. Appropriate government has been defined in S. 2(a) of the Act. The Central Government is the appropriate government only in regard to an industrial dispute concerning mines and other disputes referred to in clause (a)(1) of S. 2 of the Act. Taking the three definitions together although the two concerned workmen may come within the definition of S. 2(s) of the Act and may be entitled to all the rights under it, the special meaning of 'employment in relation to a mine' cannot be applicable to them. Therefore, the conciliation officer could not have sent a failure report to the Central Government and the latter could not have made a reference with respect to those two concerned

workmen who are not employed in relation to a mine and the Tribunal created by the Central Government has no jurisdiction to entertain a reference which concerns workmen who can't be said to be employed in a mine.

24. In this connection I may refer to the case reported in AIR 1966 S.C. 921-3 SCLJ 1800 (Sirajuddin & Co. vs. their workmen) wherein it has been held that the work which is incidental to or connected with mining operation must have some connection with or in relation to the mining operation themselves. Employees who perform work not connected with mining operation can't be said to be persons employed in the mine.

25. I may also refer to the case of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. vs. P. Venkata Swamy and others reported in 1976 Lab. I.C. 1313. The garden mazdoors and malies attached to the bungalow, filed a petition under S. 33C(2) of the Act before the Labour Court, Dhanbad. Point was raised that those employees could not be held to be employed in a mine and therefore the Central Government was not the appropriate government and the Labour Court created by the Central Government had no jurisdiction to entertain that application. Their Lordships of the Patna High Court after considering S. 2(a) of the Act, S. 2(j) and (h) of the Mines Act and various authorities on the point including the one reported in AIR 1966 S.C. 921 came to the conclusion that the employment of the workmen in the bungalow was not an employment in a portion of a mine or in relation to a mine and the appropriate government in this case could not therefore be the Central Government. The Labour Court accordingly had no jurisdiction to entertain the application and to pass an order.

26. In the case before us the two concerned workmen claim to have been employed in the Badjna Sub Area Office which by no stretch of reasoning can be said to be a mine or connected with mining operation and therefore the Central Government is not the appropriate government to make a reference and this Tribunal which has been created by the Central Government has no jurisdiction to entertain the same.

27. The other point raised before me is that no demand having been raised before the employers, copy of the letter of the union sent by the Assistant Labour Commission to the management can't assume the character of an industrial dispute and therefore this reference is incompetent. In this connection Shri T. P. Choudhury, Advocate for the employers, has referred to the case of Sindhu Resettlement Corporation Ltd. and Industrial Tribunal of Gujarat and others reported in Vol. 7 SCLJ 792 = 1968 (16) F.L.R. 307. Shri J. D. Lal has made a passing reference to the case of the management of Radio Foundation Engineering Ltd vs. State of Bihar reported in AIR 1970 Pat. 295. Question arises whether on the basis of the decision in the Sindhu Resettlement Corporation Ltd. the reference should be held incompetent or whether reliance would be placed on Patna case. This Patna case was subsequently considered in the case of the management of Nand & Samonta Co. vs. Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad (unreported) and reliance was placed on the case of Sindhu Resettlement Corporation. This case has also been followed in AIR 1970 Delhi 60 (Feddere Lloyd Corporation (P) Ltd. vs. Lt. Governor) through Under Secretary, Labour and others.

28. In the Sindhu Resettlement Case no demand was made with the management regarding reinstatement and the only demand was in respect to retrenchment compensation. The conciliation officer as it appears from the judgment of the Supreme Court perhaps reported to the Government of India that an industrial dispute did exist relating to reinstatement and payment of wages. As no demand had been made with the management with regard to the reinstatement the Supreme Court came to the conclusion that there was no industrial dispute between the employers and the employees and the reference was incompetent. Their Lordships said that :

"a mere demand to a Government without a dispute being raised by the workmen with the employer, cannot become an industrial dispute".

29. In the instant case what I find is that there is nothing on record to show that any demand was made with the employers. Shri Mazumder has stated in cross-examination that

his representation was both written and oral and he has nothing at present to show that a written representation was made before the management. He does not say if there was any proof that he made any oral representation. On the contrary, MW-1 has stated that it was for the first time by the letter of the Assistant Labour Commissioner dated 29th June, 1974, Ext. M-2, that they had come to know about the dispute. That being the position, I have no hesitation to conclude that no industrial dispute was raised with the employees by the concerned workmen and consequently the Central Government could not have made any reference for adjudication to the Tribunal and that the reference which is before me at present is accordingly incompetent.

29. So far as the discrepancy in describing the Badjna Sub Area is concerned, that is of no importance in view of the fact that the parties are aware about the exact nature of dispute and there is no ambiguity on that score.

30. Coming to the oral evidence I find that it is a case of Shri Mazumder that he was appointed in Badjna Sub Area Office on 10-1-74 and worked till 24-2-74 when suddenly he was stopped from work without any notice w.e.f. 25-2-74. But he admits that he did not receive wages for the period, has no letter of appointment in the sub area office and did not put in his attendance during that period.

31. Record of the conciliation proceeding before the Assistant Labour Commissioner had been called for and produced. He visited the sub area office on 9-9-74 and checked the staff register but did not find his name there. He also did not come across any documentary evidence that he worked in the sub area office. He of course saw one appointment letter dated 21-1-74 which Shri Mazumder told him had been filled in by him. Exts. W-1 and W-2 were also produced before him and he found that Shri Mazumder had put his signature on the dak despatch register.

32. In the written statement there is a categorical assertion regarding his signature in the dak despatch register and in view of the admission of Shri Mazumder himself it is very difficult to hold that he was appointed in the sub area office in any capacity. The wage sheet register is on record and his name is not there. The form B register has been produced and his name is not there. The attendance register has been produced and his name is not there. Therefore, there is absolutely no material for a conclusion that he was appointed in Badjna Sub Area Office as alleged. In fact he admits that there is no paper in proof of his employment in Shyampur Colliery itself. It is true that his name appears in the list sent by Shri Keder Pandey to the Area General Manager on 6-9-73, Ext. W-3/2, but the utmost that can be inferred from it is that he was employed in the Shyampur Colliery and it cannot in any manner whatsoever establish that he was appointed in the Badjna Sub Area Office. The Eastern Coal-fields Ltd. or its predecessor Coal Mines Authority Ltd. cannot be saddled with any responsibility for the act of the ex-employer. Under Section 7 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Central Government or the Government company cannot be liable for prior liabilities.

33. Taking into consideration all the available materials and the law on the point my considered opinion is that the reference is incompetent and the concerned workman have no case. Having not been employed in Badjna Sub Area Office as alleged, question of their stoppage does not arise. I don't agree with the contention that it is not open to the management to show that they have never been employed in the Badjna Sub Area Office and therefore there is no relationship of employer-employee. If what Shri J. D. Lal has contended is accepted, in that case on the terms of the reference itself an order for reinstatement with back wages would be passed. He has referred to the case reported in Vol 4 SCLJ-2307, Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. and workmen and others, in support of his contention that the Tribunal has no jurisdiction to go beyond the terms of reference and it must confine its adjudication to points of dispute referred and matters incidental thereto. Their Lordships have considered the provisions of S. 10(1)(a) and 10(4) of the Act and have come to the conclusion that it is open to the parties to show that the dispute referred to was not an industrial dispute at all and it is certainly open to them to bring out before the Tribunal the ramification of the dispute. That being the position, certainly I cannot go beyond the terms of reference but the

management cannot be precluded from showing that the concerned workmen having not been in their employment ever, there can be no industrial dispute at all.

34. The management of the Badjna Sub area of M/s. Coal Mines Authority Post Office Nirsachatti district Dhanbad did not stop Shri Jiwan Krishna Mazumder and Shyamal Kumar Roy, General Clerks, Badjna Sub Area office w.e.f. 25-2-74 as they had never been employed in the office and on the other grounds indicated above the reference is incompetent.

This is my award.

S. R. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/132/74-LRII/DIIA]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 13th October, 1977

S.O. 3325.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Bhilai Steel Plant (Mines) and their workmen.

**BEFORE THE DEPUTY GENERAL SUPERINTENDENT,
BHIHLAI STEEL PLANT AND ARBITRATOR**

In the matter of arbitration of an industrial dispute under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947, between the management of the Bhilai Steel Plant and their employer Shri B. B. Danak, represented by Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC) about the alleged discrimination in the matter of promotion to executive post.

PARTIES :

(1) Management of Bhilai Steel Plant, Bhilai
and

(2) Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC),
Nandini, District Durg.

PRESENT :

Shri V. Subramony, Deputy General Superintendent, Bhilai Steel Plant, Bhilai, and ARBITRATOR.

For employer—Shri A. K. Chaudhuri, Dy. Personnel Manager Shri S. Balakishnan, Asst. Personnel Manager, Shri S. K. Seth, Sr. Personnel Officer (Mines).

For workman—Shri C. R. Bakshi, Asst. Genl. Secretary, Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC), Nandini Mines, Dist. Durg. Shri D. K. Rao, Secretary, SKMS (AITUC) Nandini Mines, Dist. Durg. Shri B. B. Danak.

AWARD

An industrial Dispute between the management of Bhilai Steel Plant (Mines), Bhilai, and their workman represented by Samyukta Khadan Mazdur Sangh (AITUC), Nandini Mines, was referred to the undersigned for arbitration under Section 10 (A) of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government Notification No. L-26013/(2)/76 D. IV dt. 5-5-1976.

Specific matters in the dispute :

'Was any discrimination shown to Shri B. B. Danak, in the matter of promotion to executive post? If so, to what relief he is entitled to?'

Both the parties were requested on 11-6-1976 to submit their written statements and rejoinders with a copy to the opposite party latest by 30-6-1976. The parties jointly requested for extending the date for submission of written statements and rejoinders by 15 days, from 30-6-1976, which was granted. Both the parties submitted their statements on 15-7-1976 and jointly

requested for extending the date for submission of rejoinders and other documents by 10 days, from 15-7-1976, which was granted. The rejoinders were submitted by the parties on 26-7-1976. The first meeting was convened on 8-10-1976.

The Arbitration proceedings were held in my chamber in the presence of both the parties concerned in the case. As the proceedings could not be concluded for submission of the award within the prescribed period of 3 months, the period was extended up to 5th Aug '77 by mutual consent.

Shri B. B. Danak, born on 22-10-1922, who having a qualification of Intermediate, was serving as Chief Clerk in the Central Ordnance Depot under the Ministry of Defence while he applied for the post of office Supdt., advertised by the Bhilai Steel Project on 20-8-1956. He was selected for the post of Head Asst. and joined Bhilai Steel Project on deputation on 25-1-1957 alongwith others. Shri Danak gave his consent to serve with the Company, i.e. Hindustan Steel Ltd., in August 57 and he was absorbed permanently in the Hindustan Steel Ltd. on 22-6-1960 and his lien with the parent department was terminated. Shri Danak was promoted as office Supdt. on 22-4-1960 and to the post of Section Officer on 1-3-1963.

In the year 1971, while Shri Danak was working in the Rajhara Iron Ore Group of Mines, he was superseded in the Matter of promotion to the post of Asst. Personnel Officer by his Juniors, and this has been the cause of the dispute. Since then Shri Danak has been superseded by several others who were junior to him, in subsequent promotions.

The Union's contention is that in the matter of promotion, Shri Danak has been discriminated against in as much as that his claim for promotion on the basis of seniority has not been granted by the Management. The Management's contention has been that as Shri Danak does not possess the requisite qualifications, i.e. a Bachelor's degree, for the post of an executive, he has not been promoted.

In support of their case, the Union has put up the following main arguments :

(1) Shri Danak was selected and joined Bhilai Steel Project on 25-1-1957 on transfer from the Ministry of Defence to the Ministry of Steel & Mines with his service conditions in tact as he was enjoying while in the Ministry of Defence. The Ministry of Steel & Mines, Department of Iron & Steel, gave full protection to his service conditions with lien in his parent department. Later, Shri Danak was asked for option for acceptance of his service with the Company within the framework of Company's rules with the clear understanding that the service conditions will be the same and will not be less favourable than enjoyed by him in the parent department.

(2) Prior to 1971 many persons in the same line of promotion and in other departments not possessing the requisite qualification, have been promoted to the executive post in the same organization even though the qualification stipulation was in existence since 1963.

(3) Even after 1971, Shri Danak's colleagues who were promoted prior to 1971 without the requisite qualifications have been further promoted within the executive cadre itself.

(4) Shri Danak was allowed to officiate in the executive posts several times during 1966 to 1970. However, this officiating has been denied to him subsequently even though there have been cases where officiating had been granted in executive posts to people who are not graduates.

(5) Management has used the prerogative to promote some non-graduates to the executive posts and this prerogative was not used in the case of Shri Danak even though his performance has been outstanding, which tantamounts to "discrimination".

The Management has put up the following arguments in favour of their stand :

(1) Shri Danak, when he joined Bhilai Steel Project on 21-5-1956 as Section Assistant, gave a letter of willingness that his services be transferred to the Hindustan Steel Ltd., with effect from 1-8-1957. In this letter he has clearly

stipulated that he agrees to be governed by the Company's rules in force from time to time in regard to leave, travelling allowance and other allowances, provident fund etc., on the presumption that this will not be less favourable than those existing at present. There has never been any commitment that there will be no change in the service conditions regarding promotion. A person joining a new organization cannot be covered by the promotion rules of his previous employers. Promotions which affect the interests of other co-workers also and the level of efficiency must conform to the requirements of the organization where an employee is working, and as such there cannot be any question of notional application of promotion rules of the previous employer.

(2) There have been few cases in which some persons who have been found to be exceptionally good have promoted to executive cadres even though they do not possess the requisite qualifications as at that time the organization was nascent and sufficient number of qualified personnel were not available. However, after the strict instructions from Head office in the year 1968, there has not been any case where a person who is not a graduate has been promoted to the executive cadre in that particular line of promotion. It was further stated that promotions before 1968 has not affected Shri Danak, as he has not been superseded at that time.

(3) There has not been any promotion from non-executive to executive cadre after 1971. There have been isolated cases of promotion within the executive cadre, i.e. from executive to executive cadres, which was within the executive power of the Management and this has not affected Shri Danak.

(4) The instructions regarding qualifications and eligibility of the person, is fully being taken into consideration even while a person is being given officiating chance to officiate against executive posts since 1971. There have been a few cases of officiating being granted to persons without the requisite qualifications earlier, but this has been for administrative convenience so as to facilitate continuity of work. But this has not affected Shri Danak and this rule is not applicable to Shri Danak only as he also was allowed to officiate prior to 1970 against executive posts.

(5) The management has right to change the rules to suit to the needs of the organization from time to time and this power, particularly concerning the executive posts, is not questionable. The Management at the same time has certain propogatives also and his prerogative which the management has used in promoting a few people without the requisite qualifications within the executive cadre itself even after 1968, is to be understood as "prerogative". Not using the prerogative in the case of Shri Danak cannot be deemed as "discrimination."

In support of the various arguments, both the parties concerned have produced certain documents and were allowed to elaborate the various points concerned in these arguments in detail in the presence of the other party.

The observations of the undersigned on each of the arguments above are as follows :—

(1) It is agreed that the terms of service in the matter of promotion existing in a previous organizations cannot be continued in the subsequent organization as the nature of work, system, priorities etc., will be entirely different. As such, the contention that Shri Danak should have been allowed to enjoy the rules with regard to the promotion of the Ministry of Defence during his tenure in Bhilai Steel Plant, is not valid.

(2) It is established that there have been cases in which persons without requisite qualifications have been promoted to executive posts up to 1968. The Management's contention that this has been done only because the organization was new and many qualified persons with sufficient experience were not available, does not fully establish the reason for the violation of a rule on qualifications which was in existence in 1963 itself. The Union had put forward a few cases in which the Management has been changing the rules which has resulted in promotion of a few people without the requisite qualifications while denying the same to a few others prior to 1968, which, in the opinion of the undersigned, should have been avoided. However, since these actions of the Management

prior to 1968 has not caused any supersession to Shri Danak and as his claim for promotion has arisen only in the year 1971, and as during the period 1968 to 1971 and beyond 1971 there has not been any case of promotion of any one in the particular line of promotion without requisite qualifications to the executive level there has not been any cause of grievance in the matter of promotion for Shri Danak.

(3) There have been cases in which persons without requisite qualifications, who were promoted to executive level prior to 1968, have been promoted to higher levels in the executive level itself even after 1971. However, this does not affect Shri Danak nor has caused any grievance to Shri Danak, as his claim for promotion is from non-executive to executive cadre which has arisen in 1971, when he became No. 1 in the Seniority List in the particular line promotion.

(4) Officiating arrangement in the organization, as it came out during the arguments, has not been always strictly as per rules, and the circumstances under which the rules could not be strictly followed in the matter of officiating, as brought out by the Management, is logical. It was established that in an organization having various units and having small groups looking after the office work in various units, it will not be always possible to strictly follow the rules as regards officiating. However, Shri Danak has not been singled out since 1971 as regards officiating is concerned, and as Shri Danak also was given chances to officiate before 1971 alongwith others, who

do not possess the requisite qualifications had not been granted officiating after 1971, there has not been any discrimination shown to Shri Danak.

(5) Any management has certain prerogatives and these prerogatives are to be judiciously used in exceptionally deserving cases consistent with the organizational needs. Denial of the use of this prerogative power of the management in a particular case cannot be deemed as "discrimination", as use of this prerogative in all cases defeats the very essence, efficacy and purpose of this prerogative power. Even this discriminatory power has not been used to promote any one in the L.O.P. since 1968, and as the claim for promotion for Shri Danak has come, only in 1971, he has no cause for grievance.

In view of the above, it is the considered opinion of the undersigned that there has not been any discrimination shown to Shri B. B. Danak in the matter of promotion to executive post, and as such is not entitled to any relief.

The Award is given accordingly in terms stated in the earlier para.

Given the Award under my Seal and signature the thirtieth day of July, 1977.

V. SUBRAMONY, Dy. General Supdt.

Bhilai Steel Plant, Bhilai.
and Arbitrator

[No. L-26013(2)/76-DHIB]
J. C. SAXENA, Under Secy.